जम्मू लद्दाख विज़न

आर एन आई नंबर: जेकेएचआईएन/2019/78824 | पोस्टल नंबर : एल-29/जेके.579/24-26

साप्ताहिक | वर्ष : 7 | जम्मू | अंक : 1 | सोमवार जनवरी 6, 2025 | मूल्य : 3 रुपए | पेज : 16

साल 2000 से इस सीट पर बीजेडी का कब्जा, क्या बीजेपी तोड़ पाएगी यह तिलिस्म

पेज 6...

राम मंदिर बनाने वालों और राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के बीच चुनावः शाह

पेज 11...

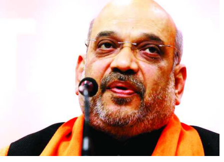

कालिंधर बस दुर्घटना पर शाम लाल गुप्ता ने गहरा शोक व्यक्त किया, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए त्वरित उपायों की मांग की

पेज 14...

कुछ लोग जाति के नाम पर समाज में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं: पीएम मोदी

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जाति के नाम पर समाज में जहर फैलाने के लिए विपक्ष पर शनिवार को हमला बोला और लोगों से गांवों की साझा संस्कृति और विरासत को मजबूत करने के उद्देश्य से ऐसी साजिशों को विफल करने को कहा।

ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार 2014 से ही ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में गांवों की अहम भूमिका होगी।

कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य भारतीय ब्लॉक नेताओं का परोक्ष जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि कुछ लोग जाति के नाम पर समाज में जहर फैलाने और सामाजिक ताने–बाने को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा, "हमें इन साजिशों को विफल करना होगा और अपने गांवों की साझी विरासत को संरक्षित और मजबूत करना होगा।"

गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्षी नेता

लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं।

मोदी ने कहा कि 2014 से वे लगातार ग्रामीण भारत की सेवा में लगे हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, "ग्रामीण भारत के लोगों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना मेरी सरकार की प्राथमिकता है।" उन्होंने कहा कि सरकार का विजन सशक्त ग्रामीण भारत सुनिश्चित करना, ग्रामीणों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना, पलायन को कम करना और गांवों के लोगों के लिए जीवन को आसान बनाना है।

गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजनाओं के बारे में बात करते हुए मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाए गए हैं और पीएम आवास योजना के तहत ग्रामीण भारत के करोड़ों लोगों को पक्के घर दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के जरिए सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, "आज डेढ़ लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।"

उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीकों की मदद से टेलीमेडिसिन ने गांवों में बेहतरीन डॉक्टरों और अस्पतालों का विकल्प सुनिश्चित किया है। उन्होंने आगे कहा कि ई–संजीवनी के जरिए ग्रामीण इलाकों में करोड़ों लोगों को टेलीमेडिसिन का फायदा मिला है।

प्रधानमंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक नीतियां बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का विजन गांवों को विकास और अवसर के जीवंत केंद्रों में बदलकर ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार की मंशा, नीतियां और फैसले ग्रामीण भारत को नई ऊर्जा के साथ सशक्त बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को करीब 3 लाख करोड़

■ शेष पेज 2...

यूपी के मुख्य सचिव ने जम्मू-कश्मीर के लोगों को प्रयागराज में महाकुंभ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

जम्मू : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शनिवार को माता वैष्णो देवी और माता भद्रकाली मंदिरों का दौरा किया और जम्मू–कश्मीर के लोगों को 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

अपनी पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रश्मि सिंह और उनके बेटे के साथ, मुख्य सचिव को जम्मू के भद्रकाली मंदिर में आयोजित एक समारोह में विस्थापित कश्मीरी पंडितों ने सम्मानित किया।

"13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री (योगी आदित्यनाथ) ने देश और दुनिया भर के लोगों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को कुंभ में आमंत्रित करते हैं, "सिंह ने संवाददाताओं से कहा। पर जोर देते सिंह ने कहा, "

■ शेष पेज 2...

डॉ. जितेंद्र ने मीडिया लंच की मेजबानी की, विभिन्न मुद्दों पर अनौपचारिक प्रतिक्रिया मांगी

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने अपने आवास पर विभिन्न ज्ञात प्रकाशनों और चैनलों के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारों के लिए एक अनौपचारिक मीडिया लंच का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अनौपचारिक प्रतिक्रिया मांगी।

डॉ. जितेंद्र सिंह पिछले कई वर्षों से नियमित अंतराल पर इस तरह के मीडिया मिलन समारोह आयोजित करते रहे हैं, आज आयोजित

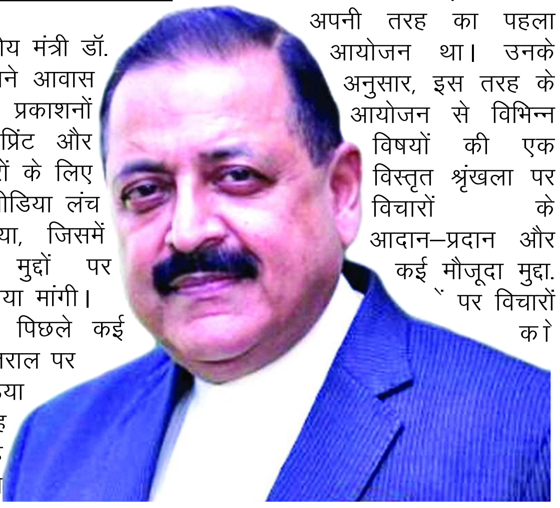

किया गया यह नए साल में अपनी तरह का पहला आयोजन था। उनके अनुसार, इस तरह के आयोजन से विभिन्न विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर विचारों के आदान–प्रदान और कई मौजूदा मुद्दों पर विचारों को साझा करने का अवसर मिलता है।

लंच मीटिंग में विचारों का जीवंत आदान–प्रदान हुआ, जिसमें पत्रकारों ने विभिन्न नीतिगत मामलों और समसामयिक मामलों पर अपने इनपुट दिए। मंत्री ने उन क्षेत्रों पर प्रतिक्रिया मांगी जहां सहयोगी प्रयासों से शासन, सार्वजनिक सेवा वितरण और सफलता की कहानियों के बारे में व्यापक जागरूकता बढ़ सकती है, विशेष रूप से वैज्ञानिक क्षेत्र में। इस संवादात्मक सत्र में सरकार की पहलों, जम्मू–कश्मीर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित राष्ट्र के विकास के व्यापक दृष्टिकोण पर गहन

■ शेष पेज 2...

कर्ण सिंह ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आह्वान किया, कहा कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भारत के ताज का हनन है

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

नई दिल्ली : वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ राजनेता कर्ण सिंह ने जम्मू–कश्मीर का राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने की मांग की है और कहा है कि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति "भारत के ताज" का "अस्वीकार्य" ह्रास है। पीटीआई वीडियोज को हाल में दिए

एक साक्षात्कार में, तीन बार के राज्यसभा सांसद और पूर्ववर्ती राज्य के सदर–ए–रियासत (संवैधानिक प्रमुख) सिंह ने संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद हुए परिवर्तनों पर भी अपनी चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा कि इस संवैधानिक परिवर्तन से पहले, पूरी बहस इस बात के इर्द–गिर्द घूमती थी कि राज्य

■ शेष पेज 2...

जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई है: सीएम उमर

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

श्रीनगर : जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में सामान्य स्थिति अभी पूरी तरह बहाल नहीं हुई है क्योंकि आतंकवादी हमले जारी हैं, लेकिन शांति स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

अमित शाह के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 ने कश्मीर के युवाओं के मन में अलगाववाद के बीज बोए थे

■ शेष पेज 2...

शेष पेज 1 से.....

कुछ लोग जाति...

रुपये की आर्थिक मदद मिली है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में कृषि ऋण की राशि में 3.5 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अब पशुपालकों और मत्स्यपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इसके अलावा, देश में 9,000 से अधिक किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने आगे रेखांकित किया कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई फसलों के लिए एमएसपी में लगातार वृद्धि की है।

मोदी ने कहा, "जब इरादे नेक हों, तो परिणाम संतोषजनक होते हैं।" उन्होंने कहा कि देश अब पिछले 10 वर्षों में की गई कड़ी मेहनत का लाभ उठा रहा है।

हाल ही में हुए एक बड़े सर्वेक्षण का हवाला देते हुए, जिसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, प्रधानमंत्री ने कहा कि 2011 की तुलना में ग्रामीण भारत में खपत लगभग तिगुनी हो गई है, जो दर्शाता है कि लोग अपनी पसंदीदा वस्तुओं पर अधिक खर्च कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पहले ग्रामीणों को अपनी आय का 50 प्रतिशत से अधिक भोजन पर खर्च करना पड़ता था, लेकिन आजादी के बाद पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पर खर्च 50 प्रतिशत से नीचे आ गया है, और अब वे अन्य इच्छाओं और जरूरतों पर खर्च कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

सर्वेक्षण से एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर प्रकाश डालते हुए, जिसमें पता चला कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच खपत का अंतर कम हुआ है, प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि पहले यह माना जाता था कि शहरी व्यक्ति गांवों के लोगों की तुलना में अधिक खर्च कर सकते हैं, लेकिन निरंतर प्रयासों ने इस असमानता को कम कर दिया है।

उन्होंने कहा कि ये उपलब्धियाँ पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान हासिल की जा सकती थीं, लेकिन आज़ादी के बाद दशकों तक लाखों गाँव बुनियादी ज़रूरतों से वंचित रहे।

उन्होंने बताया कि एससी, एसटी और ओबीसी की अधिकांश आबादी गाँवों में रहती है और पिछली सरकारों ने उनकी उपेक्षा की। इससे गाँवों से पलायन हुआ, गरीबी बढ़ी और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की खाई और चौड़ी हुई। अपने भाषण में, मोदी ने भारतीय स्टेट बैंक के एक हालिया अध्ययन का भी उल्लेख किया, जिसमें पता चला है कि भारत में ग्रामीण गरीबी 2012 में लगभग 26 प्रतिशत से घटकर 2024 में 5 प्रतिशत से भी कम हो गई है।

विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए मोदी ने कहा कि जहाँ कुछ लोग दशकों से गरीबी मिटाने के नारे लगा रहे हैं, वहीं देश अब गरीबी में वास्तविक कमी देख रहा है।

इस अवसर पर बोलते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंकों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम मुद्रा और पीएम स्वनिधि सहित 16 सरकारी योजनाओं के लिए संतृप्ति अभियान चलाया है। ग्रामीण भारत की उद्यमशीलता की भावना और सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाते हुए, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन 4 से 9 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसका विषय है 'विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण'।

महोत्सव का उद्देश्य विभिन्न चर्चाओं, कार्यशालाओं और मास्टरक्लास के माध्यम से ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाना, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करना और ग्रामीण समुदायों के भीतर नवाचार को बढ़ावा देना है।

यूपी के मुख्य सचिव...

हम उन्हें कुंभ में आमंत्रित करना चाहते हैं

पिछले डेढ़ साल से इसकी तैयारियां चल रही हैं और प्रयागराज में बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर 7,000 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।"

व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए सिंह ने कहा, "हम अगले 40–45 दिनों में कुंभ में 40 करोड़ लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं। हम जम्मू–कश्मीर के लोगों, खासकर कश्मीर के लोगों को कुंभ में आने के लिए आमंत्रित करते हैं।"

उत्तर प्रदेश में पर्यटन के बारे में बात करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि पिछले साल राज्य में 38 करोड़ पर्यटक आए थे।

सिंह ने कहा, "हमारा मोटा अनुमान है कि एक पर्यटक 4,000 से 4,500 रुपये खर्च करता है। कुंभ मेले के लिए, जहां 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, हम परिवहन, होटल, किराये, रेस्तरां, भोजन और आवास जैसे

क्षेत्रों में व्यापार और व्यवसाय में 1.5 लाख करोड़ रुपये का अनुमान लगाते हैं।" इसकी तुलना में, विनिर्माण उद्योग 2–3 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सिर्फ एक नौकरी पैदा करता है। यूपी सरकार इसे पहचानती है और यह तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उत्तर प्रदेश में हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए सबसे अधिक तीर्थ स्थल हैं, जो तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा देते हैं।

विस्थापित समुदाय के लिए मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण की कश्मीरी पंडितों की मांग पर, सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह इस मुद्दे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उठाएंगे।

डॉ. जितेंद्र ने...

चर्चा की गई। अतिथियों का स्वागत करते हुए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, ष्मुझे आज आप सभी के साथ बातचीत करने का अवसर पाकर बहुत खुशी हो रही है। लो. कतंत्र में पत्रकारों के रूप में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है और इस तरह की अनौपचारिक बातचीत एक–दूसरे को बेहतर ढंग से समझने और हमारे साझा राष्ट्रीय लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए आवश्यक है।ष्

इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरीमेंट (एसपीएडीईएक्स) मिशन को एक मील का पत्थर बताते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने एक महत्वाकांक्षी समयरेखा साझा कीरू जनवरी 2025रू नाविक में प्रगति और फरवरी में मोबाइल संचार के लिए एक अमेरिकी उपग्रह का प्रक्षेपण। 2025रू व्योममित्रा, एक महिला रोबोट, गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री जैसे कार्य करेगी। 2026रू पहला मानवयुक्त गगनयान मिशन। 2035रू भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, भारत अंतरिक्ष स्टेशन। 2040रू चंद्रमा पर उतरने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने जनता को सूचित करने और जनमत को आकार देने में मीडिया द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की। मोदी सरकार 3.0 के नए सुधारों के बारे में पूछे जाने पर, उन्होंने हाल ही में लॉन्च की गई ठप्—म्3 (अर्थव्यवस्था, रोजगार और पर्यावरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी) नीति पर प्रकाश डाला, जिसे हाल ही में प्रधान मंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह दूरदर्शी नीति भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार परिदृश्य और पर्यावरणीय स्थिरता को आकार देने की इसकी क्षमता को मजबूत करती है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और पृथ्वी विज्ञान को कवर करने वाले बीट पत्रकार भारत के अंतरिक्ष मिशन, डीप सी मिशन और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के बारे में जानना चाहते थे। ष्संपूर्ण विज्ञान, संपूर्ण सरकार और संपूर्ण राष्ट्रष् दृष्टिकोण के महत्व पर जोर देते हुए। उन्होंने डीप सी मिशन जैसी चल रही पहलों पर प्रकाश डाला, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर किया है और अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (छत्थ्), जिसे 2024 में पारित किया गया था और 2025 में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है।

कर्ण सिंह ने...

को कितनी स्वायत्तता दी जानी है। सिंह ने कहा, ष्(अनुच्छेद) 370 के निरस्त होने के बाद पूरा खेल बदल गया है।

उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तन पूर्ववर्ती राज्य का ह्रास है और यह अस्वीकार्य है। सिंह ने कहा कि अमेरिका में भारत के एक पूर्व राजदूत ने कहा कि जम्मू–कश्मीर की वर्तमान स्थिति ने इसे शासन दक्षता के मामले में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों से पीछे कर दिया है। उन्होंने कहा , (हम) तो मुकुट हैं हिंदुस्तान के उन्होंने हिमाचल प्रदेश के समान अधिवास कानूनों की भी वकालत की, जो स्थानीय लोगों को भूमि स्वामित्व तक सीमित करते हैं। उन्होंने कहा, ये वे अधिवास कानून हैं जो हम चाहते हैं। हालांकि, सिंह को लगता है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बारे में सब कुछ नकारात्मक नहीं है। उन्होंने कहा कि निरस्तीकरण ने एक ऐसे कानून को खत्म कर दिया, जो राज्य की उन महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को छीन लेता था, जिन्होंने बाहरी लोगों से शादी की थी और पाकिस्तान से पलायन करने वाले कई लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाया था। उन्होंने कहा, ष्इसलिए मैंने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण अपनाया। इसमें कुछ चीजें सकारात्मक हैं।ष् उन्होंने कहा, ष्हर कोई मेरे पास कूद पड़ा और प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। आज चीजें अलग हैं। जम्मू का अब अपना व्यक्तित्व है।ष् यह पूछे जाने पर कि क्या उनके पास अब ऐसा कोई क्रांतिकारी प्रस्ताव है, उन्होंने कहा, ष्मुझे लगता है कि अब एकमात्र क्रांतिकारी सुझाव राज्य के लोगों की सुरक्षा के लिए राज्य का दर्जा और अधिवास कानूनों की बहाली और जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के बीच उचित संतुलन बनाने का एक वास्तविक प्रयास है।ष् उन्होंने रेखांकित किया कि ऐसा करने का एकमात्र तरीका केंद्र और जम्मू–कश्मीर सरकार के बीच शांतिपूर्ण संबंध होना है। 5 अगस्त, 2019 को, केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया गया। जबकि पूर्व में सीमित अधिकारों वाली एक विधान सभा है, लद्दाख बिना किसी के काम करता है।

दशकों पहले, सिंह ने जम्मू–कश्मीर के तत्कालीन राज्य को तीन भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि जम्मू को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाना चाहिए, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाना चाहिए और कश्मीर को एक राज्य बना रहना चाहिए। जम्मू –कश्मीर की पहली विधानसभा के गठन के समय को याद करते हुए , सिंह ने कहा कि उनके पिता महाराजा हरि सिंह और उनके कई वफादारों ने सोचा था कि उन्हें ष्सद्र–ए–रियासतष की भूमिका नहीं निभानी चाहिए क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने डोगरा और महाराजा का अपमान किया था।

दिसंबर 2023 में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र के फैसले को बरकरार रखा, लेकिन राज्य का दर्जा तेजी से बहाल करने की आवश्यकता दोहराई।

साक्षात्कार के दौरान, सिंह ने अब्दुल्ला परिवार, खासकर जम्मू–कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ अपने संबंधों पर भी विचार किया।

उन्होंने शेख अब्दुल्ला को एक ष्उल्लेखनीयष् कश्मीरी नेता के रूप में वर्णित किया, जिन्होंने क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, लेकिन राजशाही और उभरती लोकतांत्रिक ताकतों के बीच ऐतिहासिक तनाव को देखते हुए उनके संबंधों की जटिलताओं को स्वीकार किया। ष्तो यहीं से एक तरह से तनाव शुरु हुआ। मुझे लगता है कि यह राजनी. ति का एक अपरिहार्य नतीजा था। आप देखिए, मुझे एहसास हुआ कि राजशाही ने अपना महत्व खो दिया है। कि भविष्य लोकतंत्र में है। मैं उस लोकतंत्र का हिस्सा बनना चाहता था, ष्उन्होंने कहा। सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को 12 साल के अंतराल के बाद राजनीति में वापस लाने का श्रेय दिया । उन्होंने कहा, ष्उधमपुर से चार चुनाव जीतने के बाद मैंने अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल दिया, जम्मू चला गया और हार गया। उसके बाद मैंने वास्तव में राजनीति छोड़ दी। मैं 12 साल तक राजनीति से बाहर रहा...उन्होंने मुझे राजनीति में वापस लाया।ष् उन्होंने राज्यसभा के लिए अपने चुनाव में एनसी के समर्थन को भी याद किया। सिंह ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को, जो अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी है, एक ष्संतुलित व्यक्तिष् के रूप में वर्णित किया, जिसमें सफल राजनीतिक भविष्य की संभावना है। पूर्व मंत्री ने कहा, ष्मुझे लगता है कि वह बहुत आगे जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि वह ऐसा करेंगे क्योंकि, आप जानते हैं, उन्हें अब दूसरा मौका मिला है।ष्

जम्मू-कश्मीर में...

और नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर में अलगाववाद के बीज बोए थे। मोदी सरकार ने न केवल घाटी में आतंकवाद को खत्म किया, बल्कि आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को भी खत्म किया।

अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, ष्मैं उस (शाह के बयान) पर कुछ नहीं कहना चाहता। (लेकिन) आज भी कुछ जगहों से हमले की खबरें आती हैं। जम्मू–कश्मीर में आज भी सामान्य स्थिति पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है। यह एक प्रक्रिया है और हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है।ष्

मुख्यमंत्री ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि जम्मू–कश्मीर का नाम बदलकर " कश्यप " किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, ष्ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मीडिया हाउस ने इसे चलाया लेकिन फिर इसे सही कर दिया। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और वैसे भी यह जम्मू–कश्मीर सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकता।ष्

बर्फबारी के पूर्वानुमान के मद्देनजर सरकार की तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर अब्दुल्ला ने कहा कि प्रशासन इससे निपटने के लिए तैयार है।

डिव कॉम ने बर्फ हटाने के अभियान के दौरान इंजीनियरिंग विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय और तालमेल पर जोर दिया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

श्रीनगर : आईटीएमएस कैमरों के कामकाज, सनतनगर में केपीटीसीएल टावरों के स्थानांतरण, बर्फ निकासी और पुनर्वास मामलों सहित कुछ जरूरी मुद्दों को हल करने के लिए, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूड़ी ने शनिवार को संबंधित विभागों और अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए, डिवकॉम ने आईटीएमएस के कामकाज में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ियों को गंभीरता से लिया जो यातायात नियमों के निर्बाध कार्यान्वयन को प्रभावित करता है और संबंधित अधिकारी को इस समस्या को तुरंत सुधारने का निर्देश दिया ताकि यातायात विभाग द्वारा सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सके। फ्लाईओवर पर यातायात के सुचारू आवागमन के लिए सनतनगर में केपीटीसीएल टावरों के स्थानांतरण के संबंध में, डिवकॉम ने नए ट्रांसमिशन टावरों के निर्माण के लिए 3 ए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के तहत भूमि।

अगले सप्ताह गीडा में प्लाट के लिए कर सकेंगे आवे. दन, सीएम योगी ने लॉन्च की थी योजना

गीडा में कालेसर-जगदीशपुर फोरलेन के किनारे कालेसर में व्यावसायिक एवं आवासीय प्लाटों की योजना लॉन्च की गई है. लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योनजा को लॉन्च किया था. यहां लगभग 350 आवासीय भूखंड निकाले जाने थे.

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) में अगले सप्ताह व्यावसायिक व आवासीय प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे. कालेसर में व्यावसायिक सेक्टर 23 में आवासीय प्लाटों के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाएगा. गीडा प्रबंधन की ओर से इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है. व्यावसायिक प्लाटों की संख्या 35 जबकि आवासीय की संख्या 45 होगी.

गीडा में कालेसर–जगदीशपुर फोरलेन के किनारे कालेसर में व्यावसायिक एवं आवासीय प्लाटों की योजना लॉन्च की गई है. लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योनजा को लॉन्च किया था. यहां लगभग 350 आवासीय भूखंड निकाले जाने थे.

इसके साथ ही व्यावसायिक प्लाट निकालने की भी योजना थी, लेकिन पहले रेरा से अनुमा.`दन के इंतजार में इस परियोजना में देरी हुई. उसके बाद विकास कार्यों के कारण आवेदन निकालने में कुछ और विलंब हुआ

35 प्लाटों के लिए आमंत्रित किये जाएंगे आवेदन

कालेसर में व्यावसायिक योजना से होगी शुरुआत कालेसर योजना की शुरुआत व्यासायिक प्लाटों से होगी. अगले सप्ताह बड़े आकार के 35 प्लाटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. ये प्लाट ई नीलामी के जरिए उपलब्ध होंगे.

इसके लगभग 15 दिन बाद आवासीय प्लाटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. सभी आवासीय भूखंडों के लिए एक साथ आवेदन निकालने की योजना नहीं है. पहले लगभग 250 प्लाट उपलब्ध होंगे.

आवासीय प्लाटों के लिए भी आवेदन आमंत्रित करने की तैयारी

सेक्टर 23 में पुरानी जमीन पर हुई प्लाटिंग कालेसर से पहले गीडा प्रबंधन सेक्टर 23 में एक पुरानी जमीन पर प्लाटिंग कर रहा है. यहां विभिन्न आकार के 45 प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे. व्यावसायिक प्लाटों के साथ ही इन आवासीय प्लाटों के लिए भी आवेदन आमंत्रित करने की तैयारी है. उसके बाद कालेसर में आवासीय प्लाट लोगों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे.

गीडा की सीईओ अनुज मलिक ने बताया कि अगले सप्ताह कालेसर में व्यावसायिक व सेक्टर 23 में आवासीय प्लाटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. इन आवेदनों के लगभग 15 दिन बाद कालेसर में आवासीय प्लाटों के लिए आवेदन निकाले जाएंगे.

हम दो बार गलती से इधर-उधर चले गए थे.. लालू के ऑफर पर नीतीश कुमार का जवाब

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वो गलती से दो बार इधर-उधर चले गए थे, लेकिन अब उन्हें कहीं नहीं जाना है. अब हम हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ-साथ देश का विकास करेंगे. हम लगातार बिहार के सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास पर काम कर रहे हैं.

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पाला बदलने वाले ऑफर को खारिज कर दिया है. शनिवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दो बार गलती से इधर–उधर हो गए थे. अब हम हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ–साथ देश का भी विकास करेंगे. लालू यादव ने नए साल पर कहा था कि अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं, तो उनके लिए दरवाजा खुला है. नीतीश कुमार को भी अपना दरवाजा खोलकर रखना चाहिए. नीतीश कुमार ने कहा कि जब बिहार ने हमें काम करने का मौका दिया तो बिहार की स्थिति बदल गई. किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है. हम दो बार गलती से इधर उधर हो गए. अब हम हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ–साथ देश का विकास करेंगे. बिहार की जनता ने हमें 24 नवंबर 2005 से काम करने का मौका दिया.

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम लगातार बिहार के सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास पर काम कर रहे हैं. लोग शाम के बाद घरों से बाहर निकलने से डरते थे. अस्पतालों में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं थी, सड़कें जर्जर थीं. शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी. अक्सर हिंदू और मुसलमानों के बीच विवादों की खबरें आती रहती थीं.

क्या कहा था लालू यादव ने?

आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने नए साल पर मीडिया से बात करते हुए कई सवालों का जवाब दिया था.

लालू से नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं. नीतीश को भी खोलकर रखना चाहिए. अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो साथ क्यों नहीं लेंगे, साथ ले लेंगे. नीतीश कुमार बीच–बीच में भाग जाते हैं, हम उन्हें माफ कर देंगे.

दिल्ली चुनाव में एआईएमआईएम की एंट्री, ओवैसी ने आप और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा- 'मुसलमानों के इलाकों में...,'

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण में उतरने का ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की सत्तारूढ आम आदमी पार्टी और बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है.

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक रस्साकशी शुरू हो गई है. एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को ऐलान किया है कि उनकी पार्टी भी दिल्ली के रण में उतरने जा रही है. इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और मुख्य विपक्षी दल बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है. ओवैसी ने न सिर्फ आरएसएस को बीजेपी और आप पार्टी की मां बताया. बल्कि यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली के उन इलाकों में कूड़ा फेंका जा रहा है, जहां मुस्लिम रहते हैं. एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी वैचारिक रूप से एक ही हैं और आरएसएस दोनों पार्टियों को मदद करता है. इनमें कोई अंतर नहीं है और दोनों ही हिंदुत्व को मानते हैं. ओवैसी ने कहा, आरएसएस ने ही बीजेपी और आप को बनाया है. आरएसएस ने जनसंघ बनाया और बाद में 1980 में बीजेपी बनी. दूसरी आप 2012–13 में बनी. यह बहुत बड़ी संस्था है. यह प्रयोगशाला में विकसित हिंदुत्व है. इसका (आप) वहीं गठन हुआ.' आप स्कूल बनवाने के नाम पर दिखावा करती है– ओवैसी ओवैसी ने दिल्ली चुनाव में पार्टी के उतरने का ऐलान करते हुए कहा कि उनकी एआईएम आईएम राष्ट्रीय राजधानी में चुनाव लड़ेगी. लेकिन वह कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला पार्टी की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में मुसलमानों के इलाकों में कूड़ा फेंका जा रहा है. ओवैसी ने कहा कि आम आदमी पार्टी यह कहकर दिखावा करती है कि उसने स्कूल और अस्पताल बनाए हैं. लेकिन विकास के दावे झूठे हैं और यह मुस्लिम इलाक. ों में देखा जा सकता है.

एआईएमआईएम चीफ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही. उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया है. दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीर सावरकर के नाम पर एक कॉलेज की आधारशिला रखे जाने से जुड़े सवाल पर ओवैसी ने कहा कि वह पीएम मोदी से पूछना चाहेंगे कि क्या एनडीए सरकार कपूर जांच आयोग के निष्कर्षों को स्वीकार करती है.

'रोजाना कट रही 50 हजार गायें, अधिकारी खा रहे पैसा', बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद जिला के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने शनिवार को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अपने ही सरकार के चीफ सेक्रेटरी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके अधीन अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं. राज्य में हर दिन हजारों गाय कट रही हैं. इसकी शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है. चारों तरफ लूट मची है और इस सबके मुखिया मुख्य सचिव हैं.

बीजेपी नेता नंदकिशोर गुर्जर ने यह बात आरडसीसी स्थित एक रेस्टोरेंट में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कही है. उन्होंने कहा कि, 'हमारी सरकार में प्रतिदिन 50 हजार गाय कट रही हैं. ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं. सब लूट मची है. इन सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं. ये मेरी हत्या की तैयारी कर चुके हैं, 9 डड की 25 पिस्टल खरीदी जा चुकी हैं.' उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे.

'हमारी चीफ सेक्रेटरी से कोई बैर नहीं लेकिन३,'

लोनी से लगातार दो बार के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने पहले किसी की गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी लेकिन आज हम दुखी हैं. यहां रोजाना हजारों की संख्या में गौ वध किया जा रहा है. उन्होंने कहा क भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है.

पुलिस अधिकारी केवल राजनीति केवल राजनीति में लगे रहते हैं. इनका कोई भी काम फील्ड पर नहीं नजर आता है. बीजेपी नेता ने कहा कि चारों तरफ लूट मची है और कमिश्नर चिल्ला कर कहते हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं.

उन्होंने कहा कि इतनी ताकत हैं चीफ सेक्रेटरी के पास कि वो हमारी बात सुनकर मेरी हत्या भी करा सकते हैं. ये मेरी हत्या कराने की तैयारी भी करा चुके हैं. इसके लिए 9 एमएम की 25 पिस्टल खरीदी जा चुकी हैं.

बीजेपी विधायक ने कहा कि हमारी चीफ सेक्रेटरी से कोई बैर नहीं है. न हम कभी मिले हैं और न ही उनसे बात होती है. उन्होंने कहा कि हम कई विधायकों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले थे. उन्होंने आश्वासन दिया था कि गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को हटाया जाएगा.

अतुल सुभाष सुसाइड केसः पत्नी, सास और साले को मिली जमानत, बेंगलुरु कोर्ट का आदेश

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने शनिवार को अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया को जमानत दे दी. अतुल सुभाष ने तलाक के लिए 3 करोड़ रुपये का भुगतान करने के दबाव के बाद आत्महत्या कर ली थी. 9 दिसंबर को वह अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे. उन्होंने 90 मिनट का एक वीडियो और 40 पन्नों का एक नोट छोड़ा था, जिसमें उनकी पत्नी और ससुराल वालों द्वारा उत्पीड़न का विवरण दिया गया था.

बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया को उसकी मां और भाई के साथ गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 और 3 (5) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है. पूछताछ के दौरान निकिता ने अपने पति के खिलाफ उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया था.

जमानत के लिए कोर्ट में की थी अपील

सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया ने मामले में जमानत के लिए बेंगलुरु की सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

उन्होंने पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय से सत्र अदालत को उनकी जमानत याचिका का निपटारा करने का निर्देश देने की अपील की थी. उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत को आज याचिका का निपटारा करने का निर्देश दिया.

14 दिसंबर को निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था, जबकि उनकी मां और भाई अनुराग को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अरेस्ट किया गया था.

सुसाइड नोट में अतुल ने लगाया था यातना का आरोप

34 वर्षीय सुभाष अतुल वैवाहिक मुद्दों के कारण अपनी पत्नी से अलग रह रहा था. उसने अपनी पत्नी, रिश्तेदारों और उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश द्वारा उत्पीड़न और जबरन वसूली के प्रयासों का विवरण देते हुए एक वीडियो और 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट छोड़ा था. उसने अपनी पत्नी और उसके रिश्तेदारों पर "झूठे" मामलों और "लगातार यातना" के माध्यम से उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था.

बता दें कि सुभाष और सिंघानिया की शादी 2019 में हुई थी. साल 2020 में उनका एक बेटा हुआ था.

दलबदलुओं का दबदबा, सिख भी सधे... कैसी है दिल्ली बीजेपी की पहली लिस्ट?

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

दिल्ली के चुनावी संग्राम में भारतीय जनता पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है. बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में दलबदलुओं का दबदबा है. सूची में 29 में से 9 ऐसे उम्मीदवार हैं, जो आप, कांग्रेस और दूसरी अन्य पार्टियों से बीजेपी में आए हैं.

दलबदलुओं के अलावा बीज.ेपी ने जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा है. उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 5 दलित, 5 वैश्य–बनिया और 3–3 जाट और ब्राह्मण को टिकट दिया गया है.

पहली लिस्ट में ये 9 दलबदलू

मंगोलपुरी (आरक्षित) सीट से बीजेपी ने राज कुमार चौहान को उम्मीदवार बनाया है. चौहान इस सीट से विधायक रह चुके हैं. मई 2011 में चौहान कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए थे. इसके बाद से ही चौहान बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं. इसी तरह शिरोमणि अकाली दल से बीजेपी में आए मनजिंदर सिंह सिरसा को राजौरी गार्डन से टिकट दिया गया है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली को बीज.ेपी ने गांधी नगर सीट से टिकट दिया है. कांग्रेस के एक और पूर्व विधायक तरविंदर मारवाह को जंगपुरा से टिकट दिया गया है. जंगपुरा सीट से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं. यहां कांग्रेस ने फरहात सूरी को उम्मीदवार बनाया है.

केजरीवाल और आतिशी सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत को बिजवासन सीट से उम्मीदवार बनाया गया है. गहलोत पहले नजफगढ़ सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं. पटेल नगर सीट से पूर्व मंत्री राज. कुमार आनंद को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है. आनंद भी दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं.

छतरपुर सीट से करतार सिंह तंवर को टिकट दिया गया है. तंवर पहले आप में थे. हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए है. बीजेपी ने बदरपुर सीट से नारायण शर्मा को उम्मीदवार बनाया है. शर्मा पहले आप से विधायक रह चुके हैं.

कांग्रेस नेता कुमारी रिंकू को सीमापुरी से टिकट दिया गया है. रिंकू पहले गोकलपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं.

लिस्ट में जाति समीकरण भी साधे

बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली सूची में जातिगत समीकरण का भी ख्याल रखा है. पार्टी ने 3 सिख उम्मीदवार उतारे हैं.

राजौरी गार्डन में मनजिंदर सिरसा, गांधीनगर में अरविंदर लवली और जंगपुरा में तरविंदर मारवाह को टिकट दिया गया है.

> **दिल्ली में जिन 29 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उनमें से 9 तो दूसरी पार्टी से आने वाले नेता हैं. बीज.ेपी ने 3 सिख, 3 जाट और 3 ब्राह्मण को भी टिकट दिया है. बीजेपी की पहली सूची में वैश्य और दलित उम्मीदवारों का दबदबा है.**

इसी तरह पार्टी ने 3 सीटों पर जाट बिरादरी से आने वाले नेताओं को जगह दी गई है. नागलोई–जाट से मुकेश शौकीन, बिजवासन से कैलाश गहलोत और नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को टिकट दिया गया है.

बीजेपी ने पहली सूची में 5 दलित को भी टिकट दिया है. मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, करोल बाग से दुष्यंत गौतम, पटेल नगर से राज कुमार आनंद, अंबेडकरनगर से खुशीराम चुनार और सीमापुरी से कुमारी रिंकू को उम्मीदवार बनाया गया है.

अनुप्रिया और आशीष पटेल ने जेपी नड्डा से की मुलाकात, यूपी सरकार पर लगाए थे ये आरोप

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री उनके पति आशीष पटेल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश प्रदेश की योगी सरकार में चल रहे रस्साकसी के बीच ये मुलाकात अहम है. दो दिन पहले ही अनुप्रिया और आशीष पटेल ने यूपी की योगी सरकार पर सीधा हमला बोला था और तमाम आरोप लगाये थे. उन लोगों ने आरोप लगाया था कि उन्हें जानबूझकर उत्तरप्रदेश के अधिकारियों द्वारा फंसाया जा रहा है.

मुलाकात से पहले अनुप्रिया पटेल ने शनिवार को सोशल साइट एक्स पर जेपी नड्डा के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट की है.

उन्होंने लिखा किआज केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डाके नेतृत्व में आयोजित मंथन शिविर में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के दृष्टिकोणको साकार करने के लिए एक समग्र और प्रगतिशील योजना पर चर्चा का अवसर मिला.

विकसित भारत 2047 पर मंथन में शामिल हुईं अनुप्रिया

उन्होंने लिखा कि इस अवसर पर वरिष्ठ नीति निर्माताओं और कार्यान्वयन एजेंसियों ने विभिन्न विषयों पर गहन चर्चा की, जिनका उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र को और अधिक समावेशी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाना है. यह मंथन हमारे देश के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त और उन्नत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

आशीष पटेल ने सीएम योगी से की थी मुलाकात

बता दें कि दिल्ली रवाना होने से पहले मंत्री आशीष पटेल ने शुक्रवार शाम कोसीएम योगी से भी मुलाकात की थी. यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली थी. उस मुलाकात में सीएम योगी ने आशीष पटेल से कहा था कि वह अनाप–शनाप बयान नहीं दे.

सीएम योगी से मुलाकात के बाद आशीष पटेल दिल्ली रवाना हो गये थे. दिल्ली में उनकी मुलाकात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई. इस अवसर पर उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल में भी मौजूद थीं.

यूपी एसटीएफ पर आशीष पटेल ने लगाए थे आरोप

बता दें कि दो दिन पहले यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (यूपी एसटीएफ) पर उनके खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया था. उन्होंने जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरोसे जान को खतरा होने का भी आरोप लगाया था. मंत्री ने कहा था कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा लिए गए सभी फैसलों की सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं. मंत्री का यह आरोप उनकी भाभी और समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाली सिराथू से विधायक और अपना दल (कमेरावादी) की नेता पल्लवी पटेल द्वारा विभागीय पदोन्नति में सेवा नियमों को दरकिनार करने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद आया था.

पल्लवी ने तकनीकी शिक्षा विभाग पर राज्य भर में विभागाध्यक्षों के 250 पदों पर पदोन्नति में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया

> **उत्तर प्रदेश प्रदेश की योगी सरकार में चल रहे रस्साकसी के बीच एनडीए में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री उनके पति आशीष पटेल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की.**

दो लोगों ने मिलकर की हत्या, सुरेश चंद्राकर मास्टरमाइंड... बीजापुर पत्रकार हत्याकांड पर पुलिस का बड़ा खुलासा

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने कहा है कि कॉल डिटेल निकालने के बाद वो आरोपियों तक पहुंच गई है. बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि हत्याकांड को महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर ने मिलकर अंजाम दिया है. पुलिस ने इस मामले में सुरेश चंद्राकर को भी मुख्य आरोपी बनाया है. आईडी ने कहा कि फिलहाल 11 सदस्यों की एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है. सुरेश चंद्राकर के तीन बैंक खाते सीज कर दिए गए हैं.

> **छत्तीसगढ़ में बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में सुरेश चंद्राकर को मुख्य आरोपी बनाया है. पुलिस ने दावा किया है कि इस हत्याकांड को महेंद्र रामटेके और रितेश चंद्राकर ने मिलकर अंजाम दिया है.**

वहीं, आरोपी की प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है और अवैध निर्माण पर भी कार्रवाई की गई है.

पुलिस ने दावा किया है कि एक जनवरी को सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश ने कॉल करके पत्रकार को बुलाया था. जैसे ही मुकेश चंद्राकर वहां पहुंचे सुरेश के सुपरवाइजर महेंद्र और भाई रितेश ने सिर पर वार कर दिया और उसके बाद चाकू से वार कर हत्या कर दी. इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे सेप्टिक टैंक में डाल दिया. दोनों ने हत्या की सूचना ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को फोन कर दी.

हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दिल्ली भाग गया था रितेश

हत्याकांड को अंजाम देने के अगले दिन रितेश बीजापुर से रायपुर होते हुए दिल्ली पहुंच गया. पुलिस ने रितेश को दिल्ली से गिरफ्तार भी कर लिया है जबकि महेंद्र और दिनेश को बीजापुर में गिरफ्तार किया गया था. पुलिस ने माना है कि घटना का मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर है. इसलिए उसे मुख्य आरोपी बनाया गया है. सुरेश चंद्राकर अभी तक फरार है, पुलिस उसके लोकेशन को ट्रेस कर रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है.

इस हत्याकांड के बाद से ही शक की सुई सुरेश चंद्राकर की ओर से घूम रही थी. इसलिए क्योंकि पत्रकार ने सड़क निर्माण को लेकर रिपोर्टिंग की थी जिसका ठेका सुरेश के पास था. माना जा रहा है कि रिपोर्टिंग से नाराज सुरेश चंद्राकर ने मुकेश को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था. इसके अलावा शव भी सुरेश के ठिकाने से ही बरामद किया गया था.

सुरेश चंद्राकर के अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर घटना के बाद पुलिस ने शनिवार को हत्याकांड के आरोपी सुरेश चंद्राकर के ठिकानों पर जेसीबी की कार्रवाई शुरू की थी.

प्रशासन सुरेश चंद्राकर के अवैध कब्जों की पहचान कर रही है और जेसीबी से गिराने का काम भी शुरू कर दिया है.

इसके अलावा पुलिस अब सुरेश चंद्राकर के काले कारनामों की कुंडली भी खंगालनी शुरू कर दी है.

वोटर लिस्ट से कैसे हटाया जाता है नाम? संजय सिंह के आरोपों का चुनाव आयोग ने दिया जवाब, आप नेता की पत्नी का दिया उदाहरण

आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया था कि डीईओ जानबूझकर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा रहे हैं. इसपर नई दिल्ली डीईओ ने कहा कि यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है और निराधार हैं. साथ ही चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट नाम हटाए जाने की सारी प्रकिया भी बताई है.

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार निर्वाचन आयोग को निशाना बनाया जा रहा है. दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर जानबूझकर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने का आरोप लगाया था. वहीं, जिला निर्वाचन अधिक.ारी नई दिल्ली ने शनिवार को आप नेता के आरोप को फैक्चुअली गलत और निराधार करार दिया है. साथ ही उदाहरण के लिए संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह के मामले पर प्रकाश डाला, जिसमें उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए आवेदन किया था.

नई दिल्ली जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोप कि आपत्तिकर्ताओं का विवरण उपलब्ध नहीं कराया. साथ ही दावा किया कि डीईओ जानबूझकर मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं हैं और निराधार हैं. डीईओ का कहना है कि भारतीय चुनाव आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, फॉर्म 7 का विवरण जिसमें आपत्तिकर्ताओं के नाम शामिल होते हैं उसे फॉर्म 10 के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर आप सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाता है.

मतदाता सूची की पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध

डीईओ ने चुनाव आयोग पर लगाए गए आरा.पों पर कहा कि जिला चुनाव कार्यालय मतदाता सूची की तैयारी और रखरखाव में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. आधारहीन दावों के साथ जनता को गुमराह करने के किसी भी प्रयास को नियमों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता की रक्षा के लिए दृढ़ता से संबो.धित किया जाएगा. इसके साथ ही डीईओ ने एक्स पर इससे फॉर्म 7 का विवरण कॉपी एटैच कर सारी जानकारी दी है.

डीईओ की ओर से साझा की गई जानकारी इस प्रकार हैरू

फॉर्म 7 का विवरण साझा करनारू भारतीय चुनाव आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार, फॉर्म 7 का सारांश, जिसमें आपत्तिकर्ताओं और आपत्तिकर्ताओं दोनों के नाम शामिल हैं, को फॉर्म 10 के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर आप सहित सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाता है. इसके अतिरिक्त, यह जानकारी सार्वजनिक पहुंच और पारदर्शिता के लिए सीईओ दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाती है. इसलिए, यह कथन कि आपत्तिकर्ताओं के नाम साझा नहीं किए जा रहे हैं, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है. मतदाता सूची से नाम हटानारू मतदाता सूची से किसी भी नाम को हटाने की प्रक्रिया ईसीआई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार सख्ती से की जाती है.

प्रक्रिया फॉर्म 7 दाखिल करने से शुरू होती है और ऐसे सभी मामलों में, बूथ लेवल ऑफिसर, बीएलओ पर्यवेक्षकों और अन्य अधिक.ारियों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गहन फील्ड सत्यापन किया जाता है. केवल नाम हटाने के लिए सूची जमा करने से नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है.

अनीता सिंह (संजय सिंह की पत्नी) का मामलारू एक विशिष्ट उदाहरण को उजागर करने के लिए, संजय सिंह राज्यसभा सांसद की पत्नी अनीता सिंह का नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए दो अलग–अलग फॉर्म 7 आवे.दन दायर किए गए थे. फील्ड सत्यापन के बाद, बीएलओ ने पाया कि वह दिए गए पते पर रह रही हैं, और दोनों फॉर्म 7 आवेदन खारिज कर दिए गए. इसके अतिरिक्त, गलत तरीके से फॉर्म 7 दाखिल करने के लिए आपत्तिकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.

योग्यता के आधार पर फॉर्म 7 को खारिज करनारू कई अन्य मामलों में, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 आवेदनों को उचित प्रक्रिया और फील्ड सत्यापन के बाद खारिज कर दिया गया है. प्रत्येक आवेदन की व्यक्तिगत रूप से जांच की जाती है और यदि वह अमान्य पाया जाता है तो उसे योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया जाता है.

झूठे आरोपरू यह आरोप कि डीईओ, नई दिल्ली, जानबूझकर वास्तविक मतदाताओं के नाम हटा रहा है, पूरी तरह से निराधार और निराधार है.

दिल्ली की इस रूट पर अब दौड़ेगी नमो भारत ट्रेन, पीएम मोदी कल करेंगे उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार, 5 जनवरी, 2025 को साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के अतिरिक्त 13 किलोमीटर के खंड का उद्घाटन करेंगे. इस उद्घाटन के साथ ही नमो भारत ट्रेनें अब दिल्ली पहुंच जं

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को दिल्ली–मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के अतिरिक्त 13 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन करेंगे. यह कॉरिडोर साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच का हिस्सा है. इस उद्घाटन के साथ नमो भारत ट्रेनें अब दिल्ली पहंच जाएगी.

फिलहाल साहिबाबाद एवं मेरठ दक्षिण के बीच दिल्ली–मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का 42 किलोमीटर लंबे हिस्से में ट्रेनों का संचालन हो रहा है. इसमें कुल नौ स्टेशन हैं.

पीएम मोदी द्वारा इस उद्घाटन के बाद अब नमो भारत कॉरिडोर 55 किलोमीटर बढ़कर हो जाएगा और इसमें कुल 11 स्टेशन होंगे.

रविवार शाम 5 बजे से, नमो भारत ट्रेनें 15 मिनट की अवधि पर जनता के लिए उपलब्ध होंगी.

दिल्ली से मेरठ जाने के लिए किराया तय हो गया है. स्टैन्ड.र्ड कोच के लिए न्यू अशोक नगर स्टेशन से मेरठ साउथ तक का किराया 150 रुपये और 225 रुपये प्रीमियम कोच के लिए किराया तय किया गया है.

दिल्ली से मेरठ तक अब 40 मिनट में पूरी होगी यात्रा

इस खंड पर रेल सेवा शुरू होने से मेरठ अब नमो भारत के माध्यम से दिल्ली जुड़ जाएगा एवं यात्रा का समय कमकर एक तिहाई रह जाएगा. यात्री मात्र 40 मिनट में इस खंड में यात्रा कर पाएंगे.

आज तक, नमो भारत ट्रेनों ने 50 लाख से ज्यादा यात्रियों को सेवा दी है, जो उनकी लोक.प्रियता और प्रभाव को दर्शाता है. अन्य सेक्शन यानी न्यू अशोक नगर–सराय काले खां और मेरठ साउथ–मोदीपुरम में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है.

नए उद्घाटन किए गए 13 किलोमीटर के सेक्शन में से 6 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत है और इसमें कॉरिडोर का एक प्रमुख स्टेशन आनंद विहार भी शामिल है, यह पहली बार है जब नमो भारत ट्रेनें भूमिगत सेक्शन में चलेंगी. इस स्ट्रेच पर दूसरा स्टेशन न्यू अशोक नगर में एक एलिवेटेड स्टेशन है. दोनों स्टेशन दिल्ली में स्थित हैं.

नमो भारत स्टेशनों को इस तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया है कि वे जहां भी संभव हो, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन जैसे मौजूदा सार्वजनिक परिवहन के साधनों से सहजता से जुड़े रहें.

चौबीसों घंटे निगरानी में लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे

नमो भारत परियोजना को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया है. आबादी के सभी वर्गों के लिए सुलभ और सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, बुजुर्गों, बच्चों, दिव्यांगजनों और महिलाओं सहित विभिन्न जनसांख्यिकी की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया गया है.

दिल्ली में आज होगी नमो ट्रेन की एंट्री, च्ड मोदी देंगे 12,200 करोड़ की योजनाओं की सौगात

नमो भारत ट्रेन की रविवार को पहली बार दिल्ली में एंट्री होगी. पीएम मोदी साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच दिल्ली-गाजियाबाद -मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही दिल्ली को करीब 12,200 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी देंगे.

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसके साथ ही रविवार को पहली बार नमो भारत ट्रेन की दिल्ली में एंट्री होगी. पीएम मोदी दोपहर करीब 12रू15 बजे दिल्ली में 12,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा भी करेंगे. नमो भारत ट्रेन में यात्रा करने और विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री दोपहर एक बजे दिल्ली के रोहिणी में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी रविवार को साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन करेंगे, जिसकी लागत करीब 4,600 करोड़ रुपये है. इस उद्घाटन के साथ ही दिल्ली को अपनी पहली नमो भारत कनेक्टिविटी मिल जाएगी. इससे दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा काफी आसान हो जाएगी और लाखों लोगों को तेज गति और आरामदायक यात्रा लाभ मिलेगा.

दिल्ली मेट्रो फेज–4 में 1200 करोड़ की योजना का उद्घाटन

प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो फेज–4 के जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच करीब 1,200 करोड़ रुपये की लागत वाले 2.8 किलोमीटर लंबे हिस्से का भी उद्घाटन करेंगे. यह दिल्ली मेट्रो फेज–4 का पहला उद्घाटन होगा. इससे पश्चिमी दिल्ली के कृष्णा पार्क, विक.ासपुरी के कुछ हिस्से, जनकपुरी समेत अन्य इलाकों को लाभ मिलेगा.

पीएम दिल्ली मेट्रो की रिठाला–कुंडली सेक्शन की रखेंगे आधारशिला

प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो फेज–4 के 26.5 किलोमीटर लंबे रिठाला–कुंडली सेक्शन की आधारशिला रखेंगे, जिसकी लागत करीब 6,230 करोड़ रुपये होगी. यह कॉरिडोर दिल्ली के रिठाला को हरियाणा के नाथूपुर (कुंडली) से जोड़ेगा, जिससे दिल्ली और हरियाणा के उत्तर–पश्चिमी इलाकों में कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय सुधार होगा

इससे लाभान्वित होने वाले प्रमुख क्षेत्रों में रोहिणी, बवाना, नरेला और कुंडली शामिल हैं, जिससे आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंच में सुधार होगा.

इसके चालू होने के बाद यह विस्तारित रेड लाइन के माध्यम से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में यात्रा को सुविधाजनक बनाएगा.

क्या आप मेरे साथ गाजा चलेंगे३ डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के आरोपी ने पत्र में क्यों लिखा ऐसा?

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश करने वाले आरोपी रयान राउथ ने फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के सामने सरेंडर करने इच्छा जाहिर की है.

उसे जेल में लिखे एक पत्र में कहा कि क्या आप शांति प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की दिशा में काम करेंगे.

मदद मांगते हुए राउथ ने पत्र में लिखा कि इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश करके निर्दोष बच्चों और परिवारों की हत्या को रोकने में मेरी मदद करेंगे?

राउथ पर फिलहाल मुकदमा चल रहा है और वो जेल में बंद है. राउथ पर डोनाल्ड ट्रंप के हमले को लेकर केस चल रहा है. राउथ के मुता.बिक, उसने अलेक्जेंडर हैमिल्टन के जीवन के बारे में रिसर्च और पढ़ाई कर रहे हैं. अलेक्जेंडर ने 1789 से 1795 तक पहले अमेरिकी ट्रेजरी सचिव के रूप में काम किया था.

क्या आप मेरे साथ गाजा चलेंगे?

राउथ ने पत्र में लिखा कि क्या आप हमारे साथ गाजा चलेंगे? क्या आप वहां बनाए गए बंधकों को वहां से आजाद कराने के बदले में हमास के सामने खुद आत्मसमर्पण करेंगे? आपके ऐसा करने से शांति की स्थिति फिर से शुरू हो सकती है.

इस युद्ध को खत्म करने की बहुत जरूरत है. लंबे समय से चल रहे इस युद्ध में बेगुनाह बच्चे और उनके परिवार के लोगों की मौत हो रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है.

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर 'इंडिया' भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट, दाखिल करेगा हस्तक्षेप अर्जी

चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आदेश दिया कि ओवैसी की ओर से दाखिल नई याचिका को इस मामले पर लंबित अन्य मामलों के साथ जोड़ा जाए. साथ ही यह भी कहा कि 17 फरवरी को उनके समक्ष मामले की सुनवाई की जाएगी.

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर विपक्ष के कई राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं. विपक्षी दलों के गठबंधन छक्‌। भी इस एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है. छक्‌। गठबंधन कोर्ट में हस्तक्षेप अर्जी दायर करेगा.

इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को लेकर हस्तक्षेप अर्जी दायर करेगा. इससे पहले कुछ विपक्षी दलों की ओर से इस एक्ट को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं.

ओवैसी की याचिका पर ैब्‌ की सहमति

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार को ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की उस याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई है, जिसमें 1991 के प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू करने की मांग की गई है. इस कानून के तहत किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को उस जैसा ही बनाए रखने की बात कही गई है, जैसा वह 15 अगस्त, 1947 के समय था.

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आदेश दिया कि ओवैसी की ओर से दाखिल नई याचिका को इस मामले पर लंबित अन्य मामलों के साथ जोड़ा जाए. साथ ही यह भी कहा कि अगले महीने 17 फरवरी को उनके समक्ष मामले की सुनवाई की जाएगी.

।प्डप्ड के प्रमुख ओवैसी की ओर से कोर्ट में पेश वकील निजाम पाशा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कोर्ट इस मुद्दे पर कई अलग–अलग याचिकाओं पर विचार कर रही है और उनकी ओर से दाखिल नई याचिका को भी इनके साथ जोड़ा जा सकता है. सीजेआई जस्टिस खन्ना ने कहा, "हम इस याचिका को भी जोड़ देंगे."

एक्ट को लेकर कई याचिकाएं एससी में दाखिल

ओवैसी ने एडवोकेट फुजैल अहमद अय्यूबी के जरिए पिछले साल 17 दिसंबर, को एक याचिका दायर की थी. हालांकि, 12 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने 1991 के इस कानून के खिलाफ इसी तरह की कई याचिकाओं पर कार्रवाई करते हुए सभी कोर्ट्स को नए केसों पर विचार करने और धार्मिक स्थलों, खासतौर पर मस्जिदों तथा दरगाहों को वापस लेने के लिए लंबित केसों में कोई अंतिरम या अंतिम आदेश पारित करने से रोक लगा दिया था.

कोर्ट की स्पेशल बेंच तब 6 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

इन याचिकाओं में वकील अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल मुख्य याचिका भी शामिल थी, जिसमें पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के अलग–अलग प्रावधानों को चुनौती दी गई थी.

दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने को कहता, मांगता था पैसे... पत्नी ने कर दी हत्या, शव के टुकड़े खेत में फेंके

कर्नाटक के उमरानी गांव में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया. महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. महिला ने पूछताछ में पुलिस को हत्या की पूरी कहानी बताई है.

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

'पति हर रोज पैसे मांगता था, न देने पर पिटाई करता था. मुझे दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था. मैं उसके प्रताड़ना से तंग आ चुकी थी. इसलिए उसकी हत्या कर, उसके टुकड़े–टुकड़े कर दिए.' ये कबूलनामा है कर्नाटक की एक महिला की. उसने बताया कि कैसे उसने अपने पति की बेरहमी से हत्या कर दी और बाद में शव के टुकड़े–टुकड़े कर पास के खेत में फेंक दिया. मामला बेलगावी जिले के चिक्कोडी तालुक के उमरानी गांव का है. पुलिस के अनुसार, यह हत्या उस समय हुई जब पति ने अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला.

चिक्कोडी में इटनाले नामक व्यक्ति की हत्या उसकी पत्नी सावित्री ने की है.

आरोप है कि इटनाले अपनी पत्नी को शारीरिक और मानसिक यातनाएं देता था और पैसों के लिए उसे दूसरे लोगों के साथ सोने के लिए मजबूर कर रहा था.

इसके अलावा, इटनाले ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद उसकी पत्नी ने यह कदम उठाया.

हत्या के बाद क्या हुआ?

सावित्री ने हत्या के बाद इटनाले के शव को दो टुकड़ों में काट दिया और उन्हें पास के खेत में फेंक दिया. इसके बाद, उसने घर के अंदर खून के धब्बों को साफ किया, मृतक के कपड़े जलाए और राख को कूड़े में फेंक दिया.

उसने अपने पति का मोबाइल फोन भी बंद कर दिया और किसी को भी इस घटना के बारे में न बताने के लिए अपनी बेटी को भी डराया.

हत्या का खुलासा कैसे?

स्थानीय लोगों ने खेत में पड़े शव को देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी.

संजीव खन्ना, बीआर गवई के बाद सूर्यकांत... 2025 में भारत को मिलेंगे 3 चीफ जस्टिस, कब-कब ऐसा हुआ?

अब तक 5 ऐसे मौके आए हैं, जब देश ने एक साथ 3 चीफ जस्टिस देखे हैं. साल 2025 में भी सुप्रीम कोर्ट को 3 चीफ जस्टिस मिलने जा रहा है. संजीव खन्ना के बाद बीआर गवई और जस्टिस

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट के लिए साल 2025 अहम रहने वाला है. एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के 7 जज इस साल रिटायर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देश को 3 चीफ जस्टिस मिलने वाला है. दरअसल, वर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना मई में रिटायर हो जाएंगे. खन्ना के बाद बीआर गवई मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, जो नवंबर 2025 तक पद पर रहेंगे.

नवंबर 2025 में चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी जस्टिस सूर्यकांत को मिलेगी. सूर्यकांत 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे. हालांकि, कोई बड़ा उलटफेर होता है तो इसमें बदलाव की संभावनाएं है. सुप्रीम कोर्ट के ये 7 जज हो रहे हैं रिटायर 2025 में जस्टिस सीटी रविकुमार, जस्टिस हृषिकेश रॉय, चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस बीआर गवई (चीफ जस्टिस) बनकर रिटायर हो रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत कुल 34 जज बनाए जा सकते हैं. वर्तमान में 33 पद ही भरे गए हैं. एक पद अभी रिक्त है. इन 7 पद के रिक्त होने से सरकार को इस साल कुल 8 पद सुप्रीम कोर्ट में भरने होंगे. 3 ब्श्र्प्, इनमें 2 का कार्यकाल 200 से कम दिन

इस साल देश को 3 चीफ जस्टिस मिलने जा रहा है. 2017 और उससे पहले 2014 में ऐसा हुआ था. इस बार जो 3 चीफ जस्टिस देश को मिल रहे हैं, उनमें से दो का कार्यकाल 200 से कम दिन है. मसलन, वर्तमान चीफ जस्टिस संजीव खन्ना करीब 185 दिन ही अपने पद पर रह पाएंगे.

इसके बाद जस्टिस बीआर गवई चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे. गवई करीब 120 दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे. गवई के बाद जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस बनने का मौका मिलेगा. सूर्यकांत का कार्यकाल एक साल से ज्यादा का रहने वाला है. 1. 2017 में देश ने एक साथ 3 चीफ जस्टिस देखे थे. 2015 में चीफ जस्टिस पद पर नियुक्त टीएस ठाकुर 3 जनवरी 2017 को रिटायर हुए थे. ठाकुर के बाद जगदीश खेहर को मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी मिली. खेहर अगस्त 2017 तक इस पद पर रहे. खेहर के बाद चीफ जस्टिस की कुर्सी दीपक मिश्रा को मिली. मिश्रा अक्टूबर 2018 तक चीफ जस्टिस रहे.

2. 2014 में भी देश में 3 चीफ जस्टिस देखने को मिला था. जुलाई 2013 में चीफ जस्टिस पद पर नियुक्त पी सदाशिवम अप्रैल 2014 तक इस पद पर रहे.

नए साल पर तिरुमाला में दर्शन करने पहुंचे गोल्डन मैन, पहना था 5 किलो सोना

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

नए साल के दिन तिरुमाला पहाड़ी पर भगवान शिव की पूजा करने पहुंचे एक भक्त ने सोने से सजे अपने शरीर के साथ सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उनका यह रूप सचमुच आकर्षक था, और उनके पहने गए सोने के आभूषणों ने वहां मौजूद सभी भक्तों को प्रभावित किया.

हैदराबाद के कोंडा विजय कुमार, जो तेलंगाना ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव हैं, करीब पांच किलो सोने के गहने पहने हुए थे. जबकि आमतौर पर महिलाएं सोने के गहनों में सजने की पसंद करती हैं, विजय कुमार का यह रूप अलग था. वे न सिर्फ सोने से सजे थे, बल्कि भगवान श्री वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुमाला आए थे.

उनके द्वारा पहने गए सोने के आभूषणों ने सबका ध्यान आकर्षित किया. तिरुमाला मंदिर में दर्शन के लिए आते समय, विजय कुमार हमेशा अपनी सोने की साज–धज में नजर आते हैं.

सोने के प्रति विजय कुमार का गहरा प्रेम

विजय कुमार ने बताया कि उनका सोने के प्रति एक खास प्रेम है, और यही वजह है कि उन्होंने इतने भारी आभूषण पहने थे. वे भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं और तिरुमाला मंदिर के नियमित दर्शनार्थी हैं. विजय कुमार का कहना था कि यह उनके भगवान के प्रति समर्पण का एक तरीका है, जिसमें सोने के गहनों को पहनकर वे अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करते हैं.

तिरुमाला में सोने से भरे रूप की चर्चा

सोने के प्रति विजय कुमार का यह प्यार कोई नई बात नहीं है.

वे अक्सर तिरुमाला मंदिर आते हैं और हर बार सोने से जुड़े कुछ खास गहने पहनते हैं. 31 दिसंबर को विजय कुमार ने श्रीविआईपी ब्रेक के दौरान तिरुमाला मंदिर का दौरा किया था, और इस बार भी उनके सोने से भरे रूप ने सभी को चौंका दिया था.

भक्ति और आकर्षण का अद्भुत मेल

विजय कुमार का यह अनोखा रूप तिरुमाला में एक चर्चा का विषय बन गया. उनके सोने से सजे शरीर ने यह साबित कर दिया है कि भक्ति और आकर्षण दोनों का एक साथ मेल हो सकता है. इस तरह के दृश्य तिरुमाला मंदिर की खूबसूरती और भक्तों के दिलों में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा को और भी बढ़ाते हैं.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर प्रक्रिया शुरू, सरकार ने परिवार को दिए विकल्प

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को निधन हुआ था. शनिवार को दिल्ली के निग.मबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया. अब उनके स्मारक को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है. केंद्र सरकार ने स्मारक के लिए कुछ जगहों के सुझाव दिए हैं. मनमोहन सिंह के परिवार को कुछ विकल्प दिए गए हैं.

केंद्र सरकार ने परिवार से कहा है कि वो दिए गए विकल्पों में से कोई एक स्थान का चयन कर लें. ताकि स्मारक का काम शुरू हो सके. हालांकि इसके लिए पहले ट्रस्ट का गठन जरूरी है. नई नीति के अनुसार जमीन केवल ट्रस्ट को ही आवंटित की जा सकती है. ट्रस्ट बनने के बाद ही स्मारक के निर्माण का काम शुरू किया जा सकता है.

यहां दी जा सकती है एक से डेढ़ एकड़ जमीन

स्मारक की जमीन के लिए ट्रस्ट आवेदन करेगा. जमीन आवंटन के बाद सीपीडब्ल्यूडी के साथ एमओयू पर दस्तखत होंगे. सूत्रों के अनुसार, मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए राजघाट, राष्ट्रीय स्मृति स्थल या किसान घाट के पास एक से डेढ़ एकड़ जमीन दी जा सकती है. शहरी विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने स्मारक के लिए राजघाट और उसके आसपास के इलाके का दौरा किया है. यह भी संभावना है कि डॉ मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए नेहरू–गांधी परिवार के नेताओं की समाधि के पास जगह दी जाए. यहां पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और संजय गांधी की समाधि है. बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है. बीते दिनोंकांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि और स्मारक के लिए स्थान नहीं ढूंढ पाना भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर किया गया अपमान है. इस पर बीजेपी की ओर से जवाब भी दिया गया था. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि कोई अपमान नहीं किया गया. आने वाले दिनों में स्मारक जरूर बनेगा. जो लोग विवाद पैदा कर रहे हैं उन्हें खुली छूट नहीं देनी चाहिए. सिख समुदाय ने आकर उनके (पूर्व पीएम मनमोहन सिंह) लिए प्रार्थना की. हमने हमेशा उनके काम की प्रशंसा की है और उनसे प्रेरणा ली है.

दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने का अभियान तेज, पुलिस में होगी बांग्ला भाषियों की नियुक्ति

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिया है. इस निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी क्षेत्र में बांग्लादेशियों की धरपकड़ तेज कर दी है. अब बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस में बांग्ला भाषियों को नियुक्त करने का फैसला किया गया है.

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को दबोचने के लिए अभियान शुरू किया है. रविवार को रंगपुरी इलाके में रह रहे आठ बांग्लादेशियों को दबोचा गया था. मंगलवार को फिर तीन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया था. दिल्ली में रह रहे बांग्लादेशियों के लेकर चिंता बढ़ती जा ही रही है. सिर्फ बंगाल ही नहीं, राजधानी दिल्ली में भी पुलिस घुसपैठियों से परेशान है. दिल्ली के उपराज्यपाल ने बांग्लदेशियों के खिलाफ अभियान शुरू करने का निर्देश दिया था.

दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों की तलाश के लिए अभियान चलाया है. यह अभियान 10 दिसंबर से चल रहा है. कई बांग्लादेशी घुसपैठिए पहले ही पकड़े जा चुके हैं. अब दिल्ली पुलिस बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू कर रही है. पुलिस की ओर से कहा गया है कि बांग्लादेशियों को ढूंढने के लिए पुलिस में बांग्लाभाषियों को नियुक्त किया जाएगा.

दिल्ली पुलिस में होगी बांग्ला भाषियों की नियुक्ति

बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस में बांग्ला भाषियों की नियुक्ति की जाएगी. दिल्ली पुलिस की बांग्लादेश सेल को फिर से सक्रिय किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, हर सेल में 5 से 10 पुलिस अधिकारी होंगे जो बांग्ला बोल सकते हैं. दिल्ली के हर पुलिस जिले में इस बांग्लादेश सेल के गठन का फैसला लिया गया है. बता दें कि बीस साल पहले दिल्ली पुलिस के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अजय राज शर्मा ने बांग्लादेश सेल का गठन किया था. इस सेल का मकसद दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करना था. लेकिन यह सेल काफी समय से निष्क्रिय है. हाल ही में दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या में बढ़ोतरी के कारण पुरानी सेल को फिर से खोलने का फैसला किया गया है.

उपराज्यपाल ने घुसपैठियों को लेकर दिया है निर्देश

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हाल ही में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने का आदेश दिया था. दिल्ली पुलिस ने इसी के तहत ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

सीएम देवेंद्र फडणवीस कल करेंगे कैबिनेट की बैठक, मंत्रियों के अगले 100 दिनों के काम का तय होगा एजेंडा

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक होगी. इस बैठक में, आगामी 100 दिन सभी विभागों के मंत्रियों को क्या-क्या करना है?

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

नए साल की शुरुआत में ही महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस एक्टिव हो गए हैं. आगामी 100 दिन सभी विभागों के मंत्रियों को क्या–क्या करना है? उनकी क्या तैयारी है? अपने विभाग को लेकर उनका रोड मैप क्या होगा? इसे लेकर सीएम फडणवीस गुरुवार, 2 जनवरी को सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की एक अहम बैठक लेंगे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई है. महाराष्ट्र सरकार की ये कैबिनेट बैठक दोपहर 12 बजे मंत्रालय में होगी.

बैठक में अगले 100 दिन के सरकार के रोड मैप पर चर्चा होगी. फडणवीस अपने मंत्रियों को अगले सौ दिन का टारगेट देंगे.इसके अलावा बीड सरपंच हत्या को लेकर चल रहे राजनीतिक घमासान, बेमौसम बारिश से हुआ किसानों का नुकसान, मराठा वर्सेस ओबीसी आरक्षण का विवाद आदि विषयों पर फडणवीस अपने मंत्रियों से चर्चा करने वाले हैं.

नगरपालिका चुनाव पर भी होगी चर्चा

आगामी 3 से 4 महीने में महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज संस्थाओं, नगरपालिका और महानगरपालिकाओं के चुनाव होंगे. इन चुनावो को लेकर लोकसभा और विधानसभा की तरह क्या रणनीति हो सकती है? उसपर भी चर्चा की जा सकती है.

इसके लिए सीएम फडणवीस अपने बीजेपी कोटे के मंत्रियों से अलग से मिल सकते हैं. इसके अलावा अलग–अलग जिलों में गार्जियन मिनिस्टर (पालक मंत्री) की नियुक्ति की जानी है, जिसे लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है या सीएम अलग से मंत्रियों से बात कर सकते हैं.

चुनाव में जीत के बाद फडणवीस बने हैं सीएम

बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति ने जीत हासिल की है. महायुति में भाजपा, शिवसेना और एनसीपी शामिल है. विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस राज्य के सीएम बने हैं. सीएम बनने के साथ ही उन्होंने ऐलान किया था कि मंत्रियों के कामों की समीक्षा होगी.

उन्होंने संकेत दिया था कि काम नहीं करने वाले मंत्रियों पर गाज भी गिर सकती है. उनके कामों के ऑडिट के आधार पर निर्णय किया जाएगा. वहीं उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा था कि मंत्रियों का कार्यकाल ढाई साल का होगा. उसके बाद काम के आधार पर उनके आगे के कार्यकाल के बारे में फैसला किया जाएगा.

मुरादाबाद गोकशी केसः उत्तर प्रदेश में अपराध का जंगल राज३कांग्रेस का बीजेपी पर निशाना

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गोकशी के आरोप में एक मुस्लिम युवक की हुई मौत के मामले ने अब सियासी रूप ले लिया है. कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है. एक शख्स पर गोकशी करने का आरोप लगा था.

शख्स का नाम शाहेदीन था. गुस्साई भीड़ ने शाहेदीन को इतना पीटा की उसकी मौत हो गई, लेकिन अब इस मामले पर कांग्रेस ने योगी सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है. कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा, उत्तर प्रदेश में अपराध का जंगल राज बन चुका है.

यह मामला 30 दिसंबर की देर रात का है. देर रात को सूचना मिली कि मंडी समिति परिसर में तीन लोग गोकशी की कोशिश कर रहे हैं. इसी के बाद पुलिस चौकी के पास गुस्साई भीड़ ने इनकी पिटाई की.

भीड़ ने इतनी पिटाई की के आरोपी शाहेदीन बुरी तरह घायल हो गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

कांग्रेस प्रवक्ता ने क्या कहा?

कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में अपराध का जंगल राज बन चुका है. अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल ने कानून व्यवस्था पर चिंता जताई थी, लेकिन सरकार है कि कानून व्यवस्था में भेदभाव कर रही है, इसी का नतीजा है कि उनके अधिकारी अपनी इच्छा के अनुसार कानून चला रहे हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून का अगर राज हो तो मॉब लिंचिंग और किसी तरह की भी घटना अपने आप रुक जाए, लेकिन सरकार ही अपरा.धियों को संरक्षण दे रही है.

क्या है पूरा मामला?

गोकशी के आरोपी शाहेदीन की मौत के बाद परिवार शोक में डूब गया है. साथ ही परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई और मुकदमा दर्ज कराया है.

पुलिस ने शाहेदीन के भाई आलम के कहने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या में केस दर्ज कर लिया है.

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हाल ही में एक गोकशी के आरोपी को भीड़ ने इतना पीटा की उसकी मौत हो गई. इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने प्रदेश की योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश में अपराध का जंगल राज बन चुका है.

संपादकीय

लोकतंत्र की परीक्षा

दक्षिण कोरिया के निलंबित राष्ट्रपति यून सुक येओल की गिरफ़्तारी के प्रयास को लेकर हुए नाटकीय गतिरा. `ध ने लोकतंत्र में न्याय, शक्ति और जन भावना के जटिल अंतर्संबंध की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। यह एक गहरे ध्रुवीकृत राजनीतिक परिदृश्य में नेताओं को जवाबदेह ठहराने की चुनौतियों के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। श्री यून के आवास के बाहर भ्रष्टाचार जांच कार्यालय (सीआईओ), पुलिस अधिकारियों और उनके वफादार सुरक्षाकर्मियों के बीच छह घंटे तक चली मुठभेड़ सरकार के उच्चतम स्तर पर न्याय की तलाश में व्यावहारिक और प्रतीकात्मक कठिनाइयों को रेखांकित करती है। जबकि गिरफ्तारी को निलंबित करने का निर्णय सुरक्षा चिंताओं के जवाब के रूप में तैयार किया गया था, यह कानून के शासन और राजनीतिक प्राधिकरण के दृष्टिकोण के बीच अंतर्निहित तनाव को भी दर्शाता है। इस मुद्दे के केंद्र में श्री यून द्वारा कानूनी सम्मन की अवहेलना है, जिसने उनके समर्थकों के उत्साह और उनके आलोचकों के न्याय को सुनिश्चित करने के दृढ़ संकल्प को बढ़ावा दिया है। उनके कार्य दुनिया भर के लोकतंत्रों के सामने एक व्यापक चुनौती का प्रतीक हैरू यह सुनिश्चित करना कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कानून के अधीन हों। फिर भी, गिरफ़्तारी के निलंबन के बाद उनके समर्थकों के बीच जश्न के दृश्य गंभीर आरोपों के बावजूद भी लोकलुभावन कथाओं की स्थायी अपील को दर्शाते हैं। सेना प्रमुख पार्क एन–सू और विशेष बल कमांडर क्वाक जोंग–ग्यून सहित वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के अभियोग से कानूनी लड़ाई और भी जटिल हो गई है। दोनों पर श्री यून की अल्पकालिक घोषणा के तहत मार्शल लॉ को लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभाने का आरोप है। उनका मुकदमा दक्षिण कोरिया की कानूनी प्रणाली की क्षमता का परीक्षण करेगा कि वह कथित विद्रोह के लिए अपने सैन्य नेतृत्व को जवाबदेह ठहरा सके। श्री यून की गिरफ़्तारी को अंजाम देने में कठिनाई एक गहरे प्रणालीगत मुद्दे को दर्शाती है। आधिकारिक शक्तियों से वंचित होने के बावजूद, वह अपने वफादार सुरक्षा तंत्र और जनता का समर्थन जुटाने की अपनी क्षमता के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रभाव बनाए रखते हैं। यह गतिरोध, जिसमें सीआईओ के सदस्य श्री यून की सुरक्षा टीम और सियोल की सुरक्षा के लिए नियुक्त एक सैन्य इकाई के साथ बातचीत में उलझे हुए थे, लोकतांत्रिक प्रणालियों में एक महत्वपूर्ण कमजोरी को उजागर करता हैरू राजनीतिक निष्ठाओं द्वारा कानूनी और संस्थागत प्रक्रियाओं को कमजोर किए जाने का जोखिम। जैसा कि सीआईओ अपने अगले कदमों पर विचार–विमर्श करता है, उसे एक नाजुक संत. ुलन कार्य का सामना करना पड़ता है। श्री यून को गिरफ्तार करने का एक और प्रयास तनाव को और बढ़ा सकता है और सामाजिक विभाजन को गहरा कर सकता है। इसके विपरीत, निर्णायक रूप से कार्य करने में विफल रहने से दक्षिण कोरिया की न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता को कम करने और सत्ता में बैठे लोगों के लिए दंड से मुक्ति की धारणा को मजबूत करने का जोखिम है। यह प्रकरण दक्षिण कोरिया के लोकतांत्रिक लचीलेपन के लिए एक लिटमस टेस्ट के रूप में कार्य करता है। यह इस सिद्धांत की पुष्टि करने का क्षण है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे उनकी पिछली या वर्तमान स्थिति कुछ भी हो। हालांकि, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न केवल कानूनी जवाबदे. ही के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, बल्कि एक सूक्ष्म दृष्टिकोण की भी आवश्यकता है जो आगे के ध्रुवीकरण की संभावना को कम करता है। आने वाले सप्ताह यह बताएंगे कि क्या दक्षिण कोरिया इस चुनौती से प्रभावी ढंग से निपट सकता है। इसका परिणाम इसकी सीमाओं से कहीं आगे तक गूंजेगा, जो न्याय की जीत या आधुनिक लोकतंत्रों की परीक्षा लेने वाली जटिलताओं का एक शक्तिशाली उदाहरण होगा।

मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने की आवश्यकता

विलियम पेरी

मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक दुनिया की जीवनदायिनी हैं, फिर भी वे एक मूक संकट का सामना कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइल्डलाइफ़ फ़ंड की 2022 की रिपोर्ट में 1970 के बाद से वैश्विक मीठे पानी के कशेरुकी आबादी में 83: की चौंका देने वाली गिरावट का खुलासा हुआ है, जो किसी भी अन्य आवास की तुलना में कहीं ज़्यादा है। प्रकृति में गिरावट का स्तर चिंताजनक है, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र जटिल हैं, जैसा कि मानव गतिविधि के प्रभाव हैं। इसलिए, कहानी अक्सर अधिक सूक्ष्म होती है।

हमारा शोध दिखाता है कि कैसे पर्यावरण डीएनए (ईडीएनए) – जीवन और मृत्यु में जीवों द्वारा छोड़े गए डीएनए – का विश्लेषण करके मीठे पानी की धाराओं, नदियों और झीलों में छिपे रहस्यों को उजागर किया जा सकता है। यह इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों की अधिक कुशल निगरानी की उम्मीद प्रदान करता है। जबकि मछलियाँ और पक्षी आमतौर पर सुर्खियों में रहते हैं, मीठे पानी की जैव विविधता एक छिपी हुई महानगर है जिसमें कम–ज्ञात निवासी हैं। मेफ़्लाइज़ और मिज जैसे मैक्रोइनवर्टेब्रेट्स, जो नंगी आँखों से दिखाई देते हैं, स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन पर दशकों से नज़र रखी जा रही है और वे हमें इस बात का अधिक प्रतिनिधि दृष्टिकोण दे सकते हैं कि मीठे पानी के आवास मानव दबावों पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहे हैं।

दुनिया के अलग–अलग हिस्सों में मानवीय गतिविधियों से अलग–अलग स्तर पर खतरा बना रहता है। उदाहरण के लिए, पूरे यूरोप में पिछली सदी में नदी के पानी की गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ है – मुख्य रूप से बेहतर स्वच्छता, गैर–औद्योगिकीकरण और बेहतर विनियमन के कारण, जिसके परिणामस्वरूप मैक्रोइनवर्टेब्रेट जैव विविधता की बहाली हुई।

लेकिन यह अच्छी खबर सिर्फ़ इतनी दूर तक ही सीमित है। 2010 के बाद से, मीठे पानी की जैव विविधता में सुधार स्थिर हो गया है। इस बीच, पुराने पर्यावरणीय दबावों की जगह नए दबाव आ रहे हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन से लेकर पुराने सीवेज सिस्टम से निकलने वाले उभरते प्रदूषक शामिल हैं।

यकीनन, मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को समझना पहले कभी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए, इस बात की व्यापक निगरानी की आवश्यकता है कि कौन सी प्रजातियाँ मौजूद हैं। यह केवल नई तकनीकों को एकीकृत करके ही संभव है – जिसमें ईडीएनए का विश्लेषण शामिल है, जो मल, बलगम और ऊतक के टुकड़ों सहित कई स्रोतों से आ सकता है – पारंपरिक निगरानी कार्यक्रमों के साथ।

वर्तमान मीठे पानी की जैव विविधता निगरानी का मुख्य भाग अपेक्षाकृत संकीर्ण समूह के जानवरों – मछली और मैक्रोइनवर्टेब्रेट्स पर केंद्रित है। मछलियों की निगरानी आमतौर पर ष्इलेक्ट्रोफिशिंगष द्वारा की जाती है, जहाँ पानी के माध्यम से एक विद्युत प्रवाह पारित किया जाता है जो अस्थायी रूप से मछलियों को अचेत कर देता है। जो भी मछलियाँ सतह पर तैरती हैं, उनकी पहचान की जाती है और उनकी गिनती की जाती है।

मैक्रोइनवर्टेब्रेट्स को बड़े पैमाने पर ष्किक–नेट सैंपलिंगष का उपयोग करके एकत्र किया जाता है, जहां एक व्यक्ति नदी में खड़ा होता है, तलछट को ऊपर उठाता है, फिर जो कुछ भी नीचे की ओर बहता है उसे जाल में पकड़ लेता है।

इन दोनों तरीकों की अपनी सीमाएँ हैं। इलेक्ट्रोफिशिंग के साथ, नदियों के बीच चालकता में अंतर के कारण, सैंपल रन के बीच धारा को स्थिर रखना मुश्किल हो सकता है। बड़ी मछलियाँ भी झटके के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए छोटी मछलियों को चूकने की संभावना होती है, जिससे पूर्वाग्रह पैदा हो सकते हैं। किक–नेट सैंपलिंग के साथ, कुछ नदी सब्सट्रेट बेहतर परिणाम दे सकते हैं, जबकि कुछ प्रजातियाँ जाल से बचने या उससे फिसलने में बेहतर होती हैं।

दोनों ही तरीकों में, कुछ साइटें बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हो सकती हैं। साइटों के बीच मानकीकरण मुश्किल हो सकता है, इसलिए परिणाम नमूना लेने वाले के अनुभव पर निर्भर हो सकते हैं। ये दृष्टिकोण समय लेने वाले, श्रम–भारी और सबसे बढ़कर, विनाशकारी भी हैं।

दूसरी ओर, ईडीएनए को पानी के नमूने से फ़िल्टर किया जा सकता है, फ़िल्टर से निकाला जा सकता है, रुचि के टैक्सोनोमिक समूह के लिए विश्लेषण किया जा सकता है, फिर ष्मेटाबारकोडिंगष नामक प्रक्रिया में अनुक्रमित किया जा सकता है। यह हमें डेटाबेस के साथ परिणामों को क्रॉस–रेफ़रेंस करने की अनुमति देता है, जिससे उस जीव की पहचान हो जाती है जिससे डीएनए आया था।

ईडीएनए का उपयोग करने के कई फायदे हैं। यह काम आसानी से मानकीकृत और स्वचालित है। नमूना संग्रह आसान है और इसके लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, जिससे नागरिक वैज्ञानिकों की भागीदारी संभव है। जीवों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला की पहचान की जा सकती है, जिसमें कई छोटे जीव भी शामिल हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पर्यावरण में कोई व्यवधान नहीं आता।

लेकिन मक्छ। विश्लेषण अपनी सीमाओं के बिना नहीं है। पारंपरिक तरीकों से अलग, जो अलग–अलग मछलियों की गिनती कर सकते हैं, मक्छ। एक युवा सैल्मन को एक वयस्क से अलग नहीं कर सकता है। इसमें समृद्ध, बहु–दशक के डेटासेट का भी अभाव है, जो विश्लेषण के पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके बनाए गए हैं। इससे वर्तमान संरक्षण नीतियों को सूचित करने के लिए मक्छ। निष्कर्षों का उपयोग करना मुश्किल हो सकता है।

इस बात पर भी चिंता जताई गई है कि नदियों में आप कई किलोमीटर ऊपर से लाए गए जीवों के ईडीएनए का पता लगा रहे हैं – जिससे आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि पूरे नदी क्षेत्र में कोई प्रजाति संकेत कहां से आया है। यह ईडीएनए को जैव विविधता परिवर्तन को समझने के लिए एक खराब उपकरण बना देगा।

हालाँकि, हमारे हालिया अध्ययन से पता चलता है कि ऐसा नहीं है। हमने उत्तरी वेल्स में कॉनवी नदी से एक वर्ष में 14 स्थानों और 19 समय बिंदुओं पर 798 पानी के नमूने लिए। हमने इंग्लैंड, स्विटजरलैंड और अमेरिका की नदियों से भी नमूने लिए। हमारे शोध से पता चलता है कि नदी में विभिन्न जीवों द्वारा बहाए गए डीएनए दूर तक नहीं जाते हैं। अधिक. ांश इतने फीके हो जाते हैं कि उन्हें सिर्फ़ एक किलोमीटर नीचे की धारा में भी नहीं पहचाना जा सकता।

यह बहुत अच्छी खबर है – चूंकि नदी में लिया गया ईडीएनए का प्रत्येक नमूना अपेक्षाकृत छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यह हमें नदी के जलग्रहण क्षेत्र में जीवों के वितरण में परिवर्तनों का पता लगाने की अनुमति देता है। इस जानकारी के साथ, शोधकर्ता यह पता लगाना शुरू कर सकते हैं कि मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्थानीय क्षेत्रों में भी जैव विविधता में गिरावट का कारण क्या है, और फिर यह पहचान सकते हैं कि इसे कैसे रोका जाए।

जैसे–जैसे ईडीएनए विश्लेषण लोकप्रिय हो रहा है, हमारे जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान और वास्तविक दुनिया के संरक्षण के बीच की खाई को पाटने के लिए काम कर रहे हैं। यूकेडीएनए वर्किंग ग्रुप जैसी पहल सहयोग को बढ़ावा देती है, जिससे हमें सरकारी एजेंसियों और पर्यावरण हितधारकों के साथ ज्ञान साझा करने का मौका मिलता है। अंतरिक्ष और समय में जैव विविधता परिवर्तनों को कैप्चर करने वाले व्यापक डेटासेट का निर्माण करके, हम ईडीएनए के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। यह नया ज्ञान प्रभावी प्रबंधन समाधान तैयार करने की कुंजी है, तथा इससे हमारे बहुमूल्य मीठे जल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उज्जवल भविष्य सुनिश्चित होगा।

(विलियम पेरी कार्डिफ विश्वविद्यालय, यूके में पोस्टडॉक्टरल रिसर्च एसोसिएट हैं, और साइमन क्रीर बांगोर विश्वविद्यालय, यूके में आणविक पारिस्थितिकी के प्रोफ़ेसर हैं।)

रूस में सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल-असद को जहर देकर मारने की कोशिश, बाल-बाल बची जान

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

सीरिया से जान बचाकर परिवार समेत रूस भागने वाले पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को जान से मारने की कोशिश की गई है. ब्रिटिश टेबलॉयड 'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक, मास्को में बशर अल असद को ज़हर देकर उनकी हत्या का प्रयास किया गया है.

सीरिया में तख्तापलट के बाद से ही असद अपने परिवार के साथ मास्को में हैं. रूस जो कि मिडिल ईस्ट में लंबे समय से उनका अहम सहयोगी रहा है, लिहाज़ा राष्ट्रपति पुतिन ने असद परिवार को मॉस्को में संरक्षण दिया है और एक अपार्टमेंट में उनके रहने की व्यवस्था की गई है. घर में ज़हर देकर मारने की कोशिश!

ब्रिटिश मीडिया ने दावा किया गया है कि मॉस्को में सीरिया के निर्वासित राष्ट्रपति बशर अल-असद को जहर देने की कोशिश की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक एक पूर्व रूसी जासूस ने दावा किया है कि असद को उनके घर में ही धीमा ज़हर दिया जा रहा था जिसके बाद रविवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई.

ब्रिटिश टेबलॉयड 'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक, असद को उनके ही घर में मारने की कोशिश हुई, इसके सबूत जब सामने आए तो हड़कंप मच गया. सवाल उठ रहे हैं कि असद के खिलाफ साजिश रचने वाला आखिर कौन है? क्या सीरिया की नई सरकार असद को रास्ते से हटाना चाहती है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है?

असद पिछले साल 8 दिसंबर से मॉस्को में व्लादीमिर पुतिन के संरक्षण में हैं. लेकिन रूस के एक पूर्व शीर्ष जासूस की ओर से चलाए जा रहे ऑनलाइन अकाउंट जनरल एसवीआर का कहना है कि बशर अल असद रविवार को बीमार हो गए थे. इसमें दावा किया गया है कि 59 वर्षीय असद का दम घुट रहा था, बार बार खांसी आ रही थी. सूत्रों को मुताबिक टेस्ट के बाद असद के शरीर से जहरीले तत्व मिलने की खबर है, रिपोर्ट के अनुसार, अपार्टमेंट में ही इलाज के बाद सोमवार को असद की हालत स्थिर हो गई. हालांकि रूसी अधिकारियों की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई.

असद को जहर देने की ये है वजह?

बशर अल-असद को जहर किसने दिया इसका खुलासा फिलहाल नहीं हो सका है लेकिन पिछले महीने यह जानकारी सामने आई थी कि उनकी पत्नी अस्मा ब्रिटेन लौटना चाहती हैं लेकिन पासपोर्ट की वैधता खत्म होने के कारण वह लंदन वापस नहीं लौट पाएंगी.

बांग्लादेश में आतंकियों को जमानत, पर हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की याचिका क्यों हुई खारिज?

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

बांग्लादेश के हिंदू संत चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका पर गुरुवार को चटगांव मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कोर्ट में सुनवाई हुई. वहां जज ने हिंदू नेता की जमानत अर्जी खारिज कर दी. परिणामस्वरूप, चिन्मय कृष्ण दास को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. बता दें कि बांग्लादेशी हिंदू नेता के पहले वकील शुभाशीष शर्मा गिरफ्तारी से बचने के लिए लंबे समय से छुपे हुए हैं. दूसरी ओर, एक अन्य वकील रवींद्र दास को सीने में दर्द के कारण कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालांकि, उनकी अनुपस्थिति में भी चिन्मयकृष्ण की जमानत की कोशिशें नहीं रुकीं. चिन्मय कृष्ण दास को अदालत में वर्चुअली पेश किया गया. इस दिन, चिन्मय मामले के दो मुख्य वकीलों की अनुपस्थिति में, वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य 11 वकीलों की एक टीम ने चिन्मय कृष्ण दास के जमानत मामले की पैरवी की, लेकिन सामूहिक प्रयासों से कोई फायदा नहीं हुआ. चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने हिंदू नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी. उन्होंने तर्क दिया कि राजद्रोह के मामले गैर-जमानती हैं.

चिन्मय दास के खिलाफ राजद्रोह का मामला

चटगांव जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नाजिम उद्दीन चौधरी ने चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला है और राजद्रोह के मामले में आजीवन सजा का प्रावधान है. यदि वे चाहते हैं कि वे हाईकोर्ट जाएं तो जा सकते हैं. दूसरी ओर, अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि चटगांव कोर्ट के फैसले के खिलाफ वे लोग हाईकोर्ट में अपील करेंगे.

गौरतलब है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के सरकार के पतन के बाद वहां 'आतंक का माहौल' है. अंतरिम सरकार के गठन के बाद से 'यूनुस सरकार की कोर्ट ' ने प्रमुख उग्रवादी नेताओं को जमानत दे दी है. लेकिन इस बार उस अदालत में साधु चिन्मय कृष्ण दास जमानत याचिका खारिज हो गई.

कोर्ट ने उग्रवादियों को दी जमानत, चिन्मय दास को क्यों नहीं?

2004 के ग्रेनेड हत्याकांड मामले में फांसी की सजा पाने वाले बीएनपी के उपाध्यक्ष अब्दुस सलाम पिंटू को कुछ दिन पहले जमानत मिल गई है. इससे पहले इसी मामले में पूर्व गृह राज्य मंत्री लुत्फुज्जमां बाबर और बीएनपी चेयरमैन तारिक रहमान को जमानत मिल चुकी है. इतना ही नहीं, यूनुस के कार्यकाल में उल्फा प्रमुख आतंकवादी परेश बरुआ की मौत की सजा को माफ कर दिया गया था. ब्लॉगर राजीव हैदर हत्याकांड में अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के प्रमुख जसीमुद्दीन रहमानी को जमानत मिल गई है, लेकिन इतने उग्रवादी नेताओं को जमानत मिलने के बावजूद चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी गयी. इसे लेकर सवाल किए जा रहे हैं.

नवंबर में चिन्मय कृष्ण दास को किया गया था गिरफ्तार

चिन्मय कृष्ण दास को पिछले साल नवंबर में बांग्लादेश एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. वह बांग्लादेश सनातन जागरण मंच और बांग्लादेश संयुक्त अल्पसंख्यक गठबंधन के प्रवक्ता हैं. चिन्मय कृष्ण दास हमेशा बांग्लादेश के हिंदुओं पर 'आतंक' और उनके अधिकारों की बात करते नजर आए हैं. उन्होंने यूनुस की अंतरिम सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश में शुरु हुई हिंदुओं की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो यूनुस सरकार ने उन पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया.

कभी थे पक्के दोस्त, अब एक-दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए अफगानिस्तान और पाकिस्तान?

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है. पाकिस्तान जो कभी तालिबान का समर्थक था लेकिन अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबान की वापसी से दोनों के समीकरण बिगड़ चुके हैं. पाकिस्तान जिसने कभी गुड तालिबान और बैड तालिबान की थ्योरी गढ़ी था वो अब तालिबान पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि धार्मिक चरमपंथियों का समर्थन करने की पाकिस्तान की रणनीति उल्टी पड़ गई है और यही वजह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं.

पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच बढ़ा तनाव

पाकिस्तान ने 24 दिसंबर को अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत पर भीषण एयर स्ट्राइक की, जिसमें कथित तौर पर महिलाओं और बच्चों सहित 46 लोग मारे गए. पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उन्होंने तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकियों को निशाना बनाया है, जिनका उद्देश्य पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और इस्लामिक शासन की स्थापना करना है. पाकिस्तान का आरोप है कि यह समूह अफगान क्षेत्र से काम कर रहा है और इसी के चलते मुल्क में बीते कुछ महीनों से आतंकी हमले बढ़े हैं.

अफगानिस्तान ने काबुल में पाकिस्तान के दूतावास के प्रभारी को भी तलब किया और हवाई हमलों के बारे में कड़ा विरोध दर्ज कराया. साथ हीतालिबान सरकार ने पाकिस्तान के कदम की निंदा करते हुए हवाई हमलों को अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन बताया और जवाबी हमले शुरू कर दिए.

यही वजह है कि अब पाकिस्तान को अपने आंतरिक राजनीतिक संकट और बीमार अर्थव्यवस्था के बीच एक प्रमुख सहयोगी के साथ बड़ी कूटनीतिक सिरदर्द का सामना करना पड़ रहा है, एक ऐसी समस्या जिसके बारे में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि देश इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता.

तनाव की असल वजह क्या है?

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच उपजे तनाव की असल वजह ऐतिहासिक है. विवाद की जड़ें अंग्रेजों द्वारा खींची गई डुरंड लाइन से जुड़ी हैं, जो 1893 में स्थापित औपनिवेशिक युग की सीमा है, जिसे लगातार अफगान सरकार ने मान्यता देने से इनकार कर दिया है.

ऑस्ट्रेलिया की नेशनल यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर के वरिष्ठ लेक्चरर नेमातुल्लाह बिज़ान का कहना है कि, 'दोनों मुल्कों के बीच मुख्य मुद्दा सीमा तनाव रहा है, जो टीटीपी के फिर से उभरने और पाकिस्तान के अनुरोध के बावजूद तालिबान सरकार की ओर से टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई से इनकार करने की वजह से और बढ़ गया है.'

डॉ. बिज़ान कहते हैं कि कि पाकिस्तान ने अफगान राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए लंबे समय से धार्मिक चरमपंथ को बढ़ावा दिया है. 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण के दौरान, पाकिस्तान ने युवा अफगान शरणार्थियों को लड़ाकों के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए धार्मिक स्कूल स्थापित किए, जिससे अफगानिस्तान पर प्रभाव बनाने में मदद मिली. हालांकि हाल के कुछ वर्षों में पाकिस्तान की यह रणनीति उल्टी पड़ गई है, क्योंकि टीटीपी जैसे चरमपंथी धार्मिक समूहों ने अपना ध्यान पाकिस्तान पर केंद्रित कर लिया है.

सिंगापुर में आरएसआईएस के सीनियर एसोसिएट फेलो अब्दुल बासित ने बताया कि पाकिस्तान और टीटीपी ने 2021 और 2022 में कमज़ोर युद्धविराम समझौते किए थे, लेकिन विश्वास की कमी और वैचारिक मतभेदों के कारण यह टूट गए.

न्यू ईयर पर यूक्रेन ने रूस की गैस सप्लाई पर लगा दिया ब्रेक, किसे होगा नुकसान?

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच कीव ने गैस सप्लाई से जुड़े ट्रांजिट समझौते पर फिर से बातचीत करने से इनकार कर दिया है. जिससे 1 जनवरी 2025 से यूरोपीय देशों में यूक्रेन के जरिए होने वाली रूसी गैस की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी गई है.

कीव के इस फैसले से एक ओर यूरोपीय यूनियन के ऊर्जा बाजार में रूस का प्रभुत्व समाप्त हो गया है, वहीं कई यूरोपीय देशों में ऊर्जा संकट पैदा होने की आशंका है, खास तौर पर ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और मोल्डोवा में, जो अपनी बिजली आपूर्ति के लिए इस ट्रांजिट रूट पर ही निर्भर थे. रूसी ऊर्जा दिग्गज गैज़प्रोम ने बुधवार को कहा कि, 'यूक्रेन की सरकारी तेल और गैस कंपनी छंजिवद्दं की ओर से 5 साल के ट्रांजिट समझौते को रिन्यू करने से इनकार करने के बाद स्थानीय समयानुसार सुबह 8 बजे यूरोप को गैस सप्लाई रोक दी गई थी. वहीं यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री जर्मन गलुशेंको ने एक बयान में कहा कि, 'हमने यूक्रेन के रास्ते से रूसी गैस की सप्लाई को रोक दिया है, यह एक ऐतिहासिक घटना है. उन्होंने कहा कि रूस अपना बाजार खो रहा है, उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा. यूरोप ने पहले ही रूसी गैस को छोड़ने का फैसला कर लिया है.

जेलेंस्की ने 2019 में यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई के लिए रूस-यूक्रेन के बीच हुई ट्रांजिट डील को रिन्यू करने से इनकार कर दिया है, कीव के इस कदम से जहां यूरोपीय यूनियन के ऊर्जा बाजार पर रूस का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, तो वहीं पूर्वी यूरोप में ऊर्जा संकट पैदा होने की आशंका है.

गैस सप्लाई रुकने से किसे ज्यादा नुकसान?

जेलेंस्की ने 2019 में यूरोपीय देशों को गैस सप्लाई के लिए रूस-यूक्रेन के बीच हुई ट्रांजिट डील को रिन्यू करने से इनकार कर दिया है, यूक्रेनी राष्ट्रपति का मानना है कि ऐसा कर वह रूस से राजस्व छीन सकते हैं जिसका इस्तेमाल मॉस्को उनके देश के खिलाफ युद्ध को फंडिंग करने के लिए कर सकता है.

कीव के इस कदम से जहां यूरोपीय यूनियन के ऊर्जा बाजार पर रूस का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, तो वहीं पूर्वी यूरोप में ऊर्जा संकट पैदा होने की आशंका है.

यूरोपीय देश जैसे- ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और मोल्दोवा अपनी बिजली आपूर्ति के लिए इस ट्रांजिट रूट पर ही निर्भर थे. ऑस्ट्रिया को यूक्रेन के जरिए रूस से अपनी अधिकांश गैस प्राप्त हो रही थी, जबकि स्लोवाकिया को सालाना लगभग 3 बीसीएम गैस इस रूट से मिल रही थी, जो इसकी मांग का लगभग दो-तिहाई है.

यूरोप को कितनी गैस निर्यात कर रहा था रूस?

फरवरी 2022 में यूक्रेन पर मास्को के आक्रमण के बाद कई यूरोपीय देशों ने रूसी गैस पर अपनी निर्भरता कम करना शुरू कर दिया. 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण से पहले, रूस ने यूरोप के पाइपलाइन प्राकृतिक गैस निर्यात का करीब 35 फीसदी आपूर्ति की थी. लेकिन अब यह गिरकर करीब 8 फीसदी ही रह गया है.

1 दिसंबर तक यूरोपीय संघ को यूक्रेन के जरिए रूस से 14 बिलियन क्यूबिक मीटर (ठब्द) से भी कम गैस प्राप्त हुई, जो 2020 में अनुबंध शुरू होने के समय सालाना 65 बीसीएम से कम थी.

गैस सप्लाई से किसकी-कितनी कमाई?

यूक्रेनी मीडिया ने यूक्रेनी जीटीएस ऑपरेटर के पूर्व प्रमुख सेरही माकोहॉन के हवाले से बताया गया है कि ट्रांजिट डील के जरिए यूक्रेन की तुलना में रूस ने काफी अधिक कमाई की है.

वोट जिहाद मामले का अब सामने आया हवाला कनेक्शन, बड़े सिंडिकेट का हुआ पर्दाफाश

वोट जिहाद मामले की जांच के दौरान ईडी ने पाया कि देशभर में कुल 255 बैंक अकाउंट्स में से मालेगांव के बैंकों में 144 करोड़ से ज्यादा की रकम आई. इस रकम को कई बेनामी हिंदू नामों के फर्जी

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के दौरान धार्मिक दंगा भड़काने, दो गुटों में आपसी मनमुटाव और टेंशन बढ़ाने और एक खास वर्ग के वोटर्स को पैसे देकर वोट दिलवाने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है. इस बड़े मामले की जांच ईडी, इनकम टैक्स के साथ कई और एजेंसियां कर रही हैं.

के पास इन जांच एजेंसियों की वो एक्सक्लूसिव कॉपी हैं, जिसमे ये पूरा रैकेट कैसे चलाया जा रहा था? कैसे काले पैसों को फर्जी एड्रेस प्रूफ और हिंदू नामों के बैंक अकाउंट के जरिये सफेद बनाया जा रहा था और उसके बाद कैसे इन बैंक के पैसों को निकालकर इन पैसों से वोट जिहाद करवाया जा रहा था, उसकी पूरी डिटेल्स है.

इस जांच को ईडी और इनकम टैक्स "ऑपरेशन रियल कुबेर" के नाम पर जांच कर रही है. इस ऑपरेशन की शुरुआत नासिक के मालेगांव के 2 बैंक की धोखाधड़ी से शुरू हुई, जो अब मुम्बई, गुजरात, दुबई, बहरीन और नेपाल तक पहुंच चुकी है.

फर्जी बैंक खातों और बेनामी लेनदेन का पर्दाफाश

मुम्बई आयकर विभाग ने बेनामी लेनदेन के तार खंगाले हैं. मालेगांव बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आयकर (आईटी) विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी बैंक खातों और बेनामी लेनदेन का पर्दाफाश किया है. 125 करोड़ रुपये से अधिक की रकम के लेनदेन से जुड़े इस घोटाले में सिराज अहमद मेनन और मोहम्मद हारून को जांच एजेंसियों ने मुख्य आरोपी बनाया है. इस ऑपरेशन रियल कुबेर की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं.

ईडी ने अपनी जांच में पाया कि देशभर में कुल 255 बैंक अकाउंट्स में से मालेगांव के बैंकों में 144 करोड़ से ज्यादा की रकम आई. इस रकम को कई बेनामी हिंदू नामों के फर्जी एड्रेसस प्रूफ बनाकर खुलवाया गया था. गिरफ्तार आरोपी सिराज मेमन, जो मालेगांव का एक व्यापारी है और जिसकी रेड रोज ट्रेडिंग कंपनी चलती थी. सिराज की कंपनी में इन नामों की कंपनियों में से बेनामी रकम ट्रांसफर की गई.

ऐसी कुल मिलाकर 104 कंपनियां हैं, जिसमें 95 प्रतिशत कंपनियों के नाम हिंदू नाम से है और इन कंपनियों में से पकड़े गए आरोपी सिराज मेमन की कंपनी रेड रोज ट्रेडिंग कंपनी में 16 करोड़ 50 लाख के करीब रकम ट्रांसफर की गई. किरीट सोमैया का आरोप है कि अभी 2 सिंडिकेट पकड़े गए हैं, जिनमें जांच के बाद रकम 2 हजार करोड़ तक जाएगी, लेकिन अभी ऐसे 8 सिंडिकेट और हैं, जो देशभर से ऑपरेट कर रहे हैं.

अब तक कि ईडी और आईटी की जांच में जो अहम बातें जांच में सामने आई हैं. उनमें 5 मुख्य पॉइंट हैं.

14 फर्जी बैंक खाते : आयकर विभाग की जांच में सामने आया है कि सिराज हारून ने सितंबर और अक्टूबर 2024 के बीच 14 बैंक खाते फर्जी नामों से खोले और इनका ऑपरेट किया. इन खातों में 112.7 करोड़ रुपयों का क्रेडिट और 111.7 करोड़ रुपये की निकासी दर्ज की गई.

खाता धारकों को कोई जानकारी नहीं : जिन लोगों के नाम पर ये खाते खोले गए. उन्होंने विभाग को दिए बयानों में कहा कि उन्हें इन खातों की जानकारी नहीं है. उन्होंने यह भी दावा किया कि खाते खोलने के फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर नकली हैं और उन्होंने संबंधित बैंक शाखाओं का कभी दौरा नहीं किया.

हवाला नेटवर्क का खुलासा : जांच में यह बात भी सामने आई कि इन खातों से धनराशि निकालकर हवाला नेटवर्क के माध्यम से महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में भेजी गई. फंड ट्रांसफर 21 खातों के माध्यम से 175 बैंक शाखाओं से किया गया, जो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों तक फैला हुआ था.

बेनामी संपत्तियों की जांच : आयकर विभाग ने बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम के तहत चॉइस मार्केटिंग के मालिक प्रतीक जाधव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम की ओर से अजमेर शरीफ में चढ़ाई चादर, मोदी ने संदेश में कही ये बात

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब नवाज के 813 वें उर्स मुबारक के अवसर पर दुनिया भर में उनके अनुयायियों और अजमेर शरीफ में आए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी है. शनिवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम की ओर से गरीब नवाज पर चादर चढ़ाई.

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाई. 13वीं सदी के सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स समारोह का हिस्सा रहे इस कदम को रिजिजू ने "एकता और भाईचारे" का प्रतीक बताया. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब नवाज के 813 वें उर्स मुबारक के अवसर पर दुनिया भर में उनके अनुयायियों और अजमेर शरीफ में आए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं. पीए मोदी ने अपने संदेश में कहा कि समाज में प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने के लिए समर्पित उनका जीवन और आदर्श हमारी पीढियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा.

उनके वार्षिक उर्स का उत्सव लोगों में आपसी जुड़ाव को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगा. दूसरी ओर, मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पल को साझा किया और लिखा, "यह भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत और सद्भाव और करुणा के स्थायी संदेश के प्रति गहरे सम्मान का प्रतिबिंब है."

रिजिजू ने पीएम की ओर से चढ़ाई चादर

उन्होंने कहा, "यह चादर पीएम मोदी के शांति, सद्भाव और एकता के संदेश का प्रतिनिधित्व करती है. दरगाह एक ऐसी जगह है जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ आते हैं और एकजुट भारत के विचार को मजबूत करते हैं.

उन्होंने कहा कि हम यहां आने के लिए भाग्यशाली हैं. हम पीएम मोदी की ओर से चादर लेकर आए हैं. मैंने पीएम मोदी का संदेश भी पढ़ा कि हम सभी भाईचारे की भावना से अपने समाज, देश और विश्व शांति के लिए काम करेंगे. हमने यहां दुआ मांगी.

11वीं बार पीएम मोदी की ओर से चढ़ाई चादर

सद्भाव की परंपरापदभार संभालने के बाद से पीएम मोदी ने सालाना अजमेर शरीफ दरगाह पर 'चादर' भेजने की परंपरा को बनाए रखा है. यह 11वीं बार है जब प्रधानमंत्री ने इस अनुष्ठान में भाग लिया है, जो सांस्कृतिक और धार्मिक एकजुटता के एक सेतु के रूप में इसके महत्व को रेखांकित करता है. दरगाह पर दिए गए संदेश में, रिजिजू ने एक शांतिपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट करते हुए कहा, "उर्स के इस पावन अवसर पर, हम देश में सौहार्दपूर्ण माहौल की आशा करते हैं. दरगाह में सभी का, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, स्वागत है. यह हमारे राष्ट्र की विविधता और एकता का प्रतीक है. इस कार्यक्रम में देश भर से और उसके बाहर से हजारों तीर्थयात्री आए, सभी ने संत की प्रेम, करुणा और समानता की शिक्षाओं का स्मरण किया. रिजिजू ने उर्स के दौरान हर साल दरगाह पर आने वाले लाखों लोगों के लिए तीर्थयात्रा के अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के लिए चल रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगंतुकों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान कोई कठिनाई न हो.

चीन सीमा तक 100 की.मी. रफ्तार से पहुंचेगी ट्रेन, नॉर्थ ईस्ट के लिए भारतीय रेलवे ने की बड़ी तैयारी

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नार्थ ईस्ट में भारतीय रेल ने बड़ी तैयारी की है. चीन से सटे इलाकों तक ट्रैक बिछाने का काम तेजी से चल रहा है. रेलवे का दावा है कि कम समय में नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में अधिक दूरी तय किया जा सकेगा. रेलवे के ने बताया कि पहाड़ी इलाके होने के बावजूद रेलवे की ओर से ऐसे ट्रैक बनाए जा रहे हैं जिससे कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनों का परिचालन हो सके.

तिब्बत की सीमा पर सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण दो बिन्दु– नाथू ला और तवांग तक रेलवे लाइन बिछाने की परियोजनाएं चल रही है. आंकड़ों के अनुसार, 01 अप्रैल 2025 तक कुल 1368 किलोमीटर लंबी और 74 हजार 972 करोड़ रुपए लागत वाली 18 परियोजनाएं (13 नई लाइनें और 5 दोहरीकरण) निर्माण चरण में हैं, जिनमें से मार्च 2024 तक 313 किलोमीटर लंबी परियोजनाएं चालू हो गई है और 40 हजार 549 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है.

तेजी से हो रहा है विद्युतीकरण

भारत के सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र की कठिन पहाड़ी भौगोलिक चुनौतियों का सामना करते हुए भारतीय रेलवे चट्टानों को तोड़ कर, पहाड़ को चीर कर और नदियों को लांघ कर तेजी से आठों राज्यों को रेल नेटवर्क का विस्तार एवं विद्युतीकरण करने में जुटी है. बीते दस साल में पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे के विकास की रफ्तार ढाई गुना बढ़ी है. पूर्वोत्तर क्षेत्र में रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का भारतीय रेल के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) जोन क्रियान्वयन कर रहा है.

यदि 21 वीं सदी में रेलवे की प्रगति के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि 2009–14 के दौरान औसतन हर साल 2122 करोड़ रुपए आवंटित किए गए. वहीं, 66.6 किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से 333 किलोमीटर नेटवर्क का विस्तार किया गया. जबकि साल 2024–25 तक सालाना आवंटन लगभग 5 गुना बढ़ा कर 10 हजार 376 करोड़ रुपए कर दिया गया और 172.8 किलोमीटर हर साल के हिसाब से 1728 किलोमीटर नई लाइनें बिछाई गई. इस हिसाब से 2014 के बाद से पूर्वोत्तर क्षेत्र में आवंटन और काम ढाई गुना अधिक रहा है.

प्रधानमंत्री का है विशेष ध्यान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नार्थ ईस्ट को भारत का ग्रोथ इंजन बताया. पूर्वोत्तर के आठ राज्यों दृ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा को अष्टलक्ष्मी कह कर संबोधित किया है. वहीं, पूर्वोत्तर क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं में ताजा प्रगति असम के दरांग जिले से गुजरने वाली अगथोरी–डेकारगांव (155 किलोमीटर) नई रेल लाइन परियोजना में हुई है. इस परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे को मंजूरी दे दी गई है.

अरुणाचल में नाहरलागुन तक रेलवे लाइन पहुंची

इसी तरह से भैरवी–साईरंग रेल परियोजना पूर्ण होने की ओर अग्रसर है जिससे मिजोरम को निर्बाध रेल संपर्क मिलेगा. अगरतला को ब्रॉडगेज कनेक्टिविटी मिली और अगरतला से बांग्लादेश के अखौरा तक सीमापार लाइन भी बन चुकी है. हालांकि, पड़ोसी देश के राजनीतिक हालात बदलने से फिलहाल कोई आशा नहीं है. नागालैंड में 100 साल के बाद में दूसरा ब्रॉडगेज रेलवे स्टेशन बना. मणिपुर में खोंगसांग तक रेलवे लाइन पहले ही पहुंच चुकी है.

वहीं, अरुणाचल प्रदेश में नाहरलागुन तक रेलवे लाइन पहुंच चुकी है. इसी तरह सिक्किम के रंगपो को पश्चिम बंगाल के सिवाक से जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है. करीब 45 किलोमीटर लंबी सिवोक–रंगपो लाइन सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरेगा.

शिवम दुबे दूसरी बार बने पिता, पत्नी ने बेटी को दिया जन्म, रखा ये नाम

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

भारतीय टीम के ऑलराउंडर शिवम दुबे दूसरी बार पिता बने गए हैं. उनकी पत्नी अंजुम खान ने बेटी को जन्म दिया है. दोनों की शादी साल 2021 में हुई थी. वहीं 2022 में पहली बार बेटे का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और अब 2 साल के बाद उनके घर नन्ही परी आई है.

भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर शिवम दुबे के घर फिर से बच्चे की किलकारी गूंजी है. अब उनका परिवार भी रोहित शर्मा की तरह 3 से बढ़कर 4 हो गया है. वो दूसरी बार पिता बने हैं. उनकी पत्नी अंजुम खान ने बेटी को जन्म दिया. इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी है. शिवम ने शनिवार 4 जनवरी की शाम को इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि उनके घर 'नन्ही परी' आई है और इसके साथ ही उनका परिवार भी बढ़ गया है. बता दें शिवम पहली बार 2022 में पिता बने थे. तब उनकी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया था. शिवम दुबे ने अपनी बेटी के जन्म के बारे में जानकारी देते हुए उसका नाम भी बताया. उन्होंने खास पोस्ट में खुलासा करते हुए लिखा कि 'लड़की हुई है।हमारा परिवार अब 4 लोगा. ` का हो गया है. प्लीज मेहविश शिवम दुबे का स्वागत करें.' इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी नन्ही बच्ची का नाम 'मेहविश' रखा है. इस नाम का मतलब चांद जैसा सुंदर या चमकता सितारा होता है. शिवम के बेटे का नाम अयान है, जिसका मतलब आशिर्वाद होता है.

शिवम दुबे और अंजुम खान कई साल तक एक–दूसरे डेट करने के बाद साल 2021 में शादी की थी. उन्होंने जब ये बात अपने फैंस से शेयर की तो उन्हें काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. इसके पीछे वजह ये थी कि उनकी पत्नी मुस्लिम हैं और वो हिंदू. हालांकि, इसका असर उन्होंने कभी खुद पर अपनी जिंदगी पर नहीं पड़ने दिया.

शिवम दुबे ने साल 2019 में टीम इंडिया के लिए टी20 और वनडे डेब्यू किया था. हालांकि, इसके बाद वो सिर्फ 4 वनडे मैच ही खेल पाए. लेकिन टी20 टीम का लगातार हिस्सा बने रहे. टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भी वो भारतीय टीम का अहम हिस्सा था.

ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी क्रिकेटर ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ ऐसा करने वाला पहला गेंदबाज

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के आखिरी मैच में ऑस्ट्रेलिया का सबसे सफल गेंदबाज एक आदिवासी क्रिकेटर रहा. इस गेंदबाज ने सिडनी टेस्ट में कुल 10 विकेट अपने किए और एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इस सीरीज में ये खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे सफल गेंदबाज भी रहा.

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

बॉर्डर–गावस्कर ट्रॉफी 2024–25 का आखिरी मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है. सीरीज में 1–2 से पीछे चल रही टीम इंडिया की बल्लेबाजी इस मुकाबले में भी काफी खराब रही. भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 185 रन बनाए थे. लेकिन दूसरी पारी में वह 157 रनों पर ही ढेर हो गई. हालांकि भारतीय टीम ने पहली पारी में 4 रनों की बढ़त भी हासिल की थी. ऐसे में उसने ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 162 रनों का टारगेट रखा. भारतीय बल्लेबाजी का इतना बुरा हाल होने की सबसे बड़ी वजह ऑस्ट्रेलिया का एक आदिवासी क्रिकेटर रहा, जिसके आगे कोई भी बल्लेबाज नहीं चल सका.

ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी क्रिकेटर ने रचा इतिहास

टीम इंडिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट बोलैंड सबसे सफल गेंदबाज रहे. स्कॉट बोलैंड ने 16.5 ओवर में सिर्फ 45 रन दिए और 6 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया. उन्होंने यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, विराट कोहली, नीतीश रेड्डी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को पवेलियन का रास्ता दिखाया.

स्कॉट बोलैंड ने पहली पारी में भी कमाल का खेल दिखाया था. उन्होंने 20 ओवर में 31 रन देकर 4 विकेट लिए थे. यानी पहली पारी में भी वह अपनी टीम के सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं.

स्कॉट बोलैंड ने मुकाबले की दोनों पारियों को मिलाकर कुल 10 विकेट अपने नाम किए और सिर्फ 76 रन ही दिए. इसी के साथ स्कॉट बोलैंड ने भारत के खिलाफ सिडनी टेस्ट में बेस्ट प्रदर्शन का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. इससे पहले साल 2000 में ग्लेन मैक्ग्रा ने सिडनी में भारत के खिलाफ 103 रन देकर 10 विकेट लिए थे. स्कॉट बोलैंड ने भी 10 विकेट ही लिए हैं, लेकिन उन्होंने ग्लेन मैक्ग्रा से कम रन खर्च किए हैं. बता दें, स्कॉट बोलैंड ऑस्ट्रेलिया के एक आदिवासी क्रिकेटर हैं. जेसन गिलेस्पी के बाद ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट खेलने वाले स्कॉट बोलैंड सिर्फ दूसरे आदिवासी मेंस क्रिकेटर ही हैं.

ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे सफल गेंदबाज

स्कॉट बोलैंड इस सीरीज में टीम की पहली पसंद नहीं थे. लेकिन उन्हें जोश हेजलवुड की जगह खेलने का मौका मिला और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया. स्कॉट बोलैंड ने इस सीरीज में भले ही 3 मैच खेले, लेकिन वह 21 विकेट अपने नाम करने में कामयाब रहे. उन्होंने 13.19 के औसत से ये विकेट लिए. वह बॉर्डर–गावस्कर ट्रॉफी 2024–25 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं. उससे सिर्फ पैट कमिंस ही आगे हैं. पैट कमिंस ने कुल 25 विकेट लिए, लेकिन उन्होंने स्कॉट बोलैंड के मुकाबले 2 मैच ज्यादा खेले.

प्रसिद्ध कृष्णा ने झटका क्रिकेट के इतिहास का सबसे अनोखा विकेट, पहली बार घटी ये

सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने एक अनोखा विकेट हासिल किया. प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के दौरान एक ऐसा कारनामा कर दिखाया, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले कोई भी गेंदबाज नहीं कर सका था.

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट में तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को खेलने का मौका मिला. बॉर्डर–गावस्कर ट्रॉफी 2024–25 में ये उनका पहला मुकाबला था. उन्हें आकाश दीप की जगह टीम में शामिल किया गया. वह इस बड़े मौके का पूरा फायदा उठाने में कामयाब रहे. प्रसिद्ध कृष्णा ने सिडनी टेस्ट की पहली पारी में 3 विकेट लिए थे. वहीं, दूसरी पारी में भी उनका दमदार प्रदर्शन देखने को मिला. दूसरी पारी के दौरान उन्होंने एक अनोखा विकेट भी हासिल किया, जो इससे पहले कोई भी गेंदबाज हासिल नहीं कर सका था.

प्रसिद्ध कृष्णा ने झटका सबसे अनोखा विकेट

प्रसिद्ध कृष्णा सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन पहले सेशन में सबसे सफल गेंदबाज रहे. 162 रनों के टारगेट को डिफेंड करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती तीन विकेट गिराए. उन्होंने सैम कॉन्सटस, मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ को अपना शिकार बनाया. लेकिन स्टीव स्मिथ का विकेट उनके लिए सबसे खास रहा. स्टीव स्मिथ इस पारी में 9 गेंदों पर 4 रन ही बना सके और प्रसिद्ध कृष्णा का शिकार बने. बता दें, मुकाबले की पहली पारी में भी प्रसिद्ध कृष्णा ने ही स्टीव स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाया.

बता दें, सिडनी टेस्ट की दूसरी पारी में सस्ते में आउट होने के बाद स्टीव स्मिथ एक बार फिर टेस्ट में अपने 10 हजार रन पूरे करने से चूक गए. स्टीव स्मिथ को टेस्ट में 10 हजार रन का आंकड़ा छूने के लिए अभी भी 1 रन की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें अब अगली सीरीज तक इंतजार करना होगा. यानी स्टीव स्मिथ जब 9999 पर थे, तब प्रसिद्ध कृष्णा ने उनका विकेट हासिल किया और स्मिथ का इंतजार और लंबा कर दिया.

बता दें, इसी के साथ प्रसिद्ध कृष्णा पहले ऐसे गेंदबाज बन गए जिसने किसी बल्लेबाज को 9999 टेस्ट करियर रन पर आउट किया.

हरभजन सिंह की फैन से हुई बहस, रोहित के बहाने एमएमस धोनी को बनाया निशाना

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा के खुद को ड्रॉप करने के फैसले को लेकर बहस छिड़ी हुई है. इसको लेकर ही सोशल मीडिया पर भी चर्चा चल रही थी, जहां कुछ क्रिकेट फैंस ने रोहित पर सवाल खड़े कर दिए और फिर हरभजन ने उन्हें अपने अंदाज में जवाब दिया.

टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और अपने दिल की बात रखने से नहीं चूकते. हालांकि, कई बार ऐसे में उनका गर्म मिजाज भी सामने आ जाता है और वो झगड़ों में उलझ जाते हैं. मैदान पर तो कई बार ऐसा देखने को मिला था लेकिन अब सोशल मीडिया पर भी कभी–कभार ऐसा देखने को मिल जाता है. एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ है, जहां उनकी एक क्रिकेट फैंस से बहस हो गई. ये बहस टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर हुई, जिन्हें सिडनी टेस्ट से ड्रॉप किया गया था. इस बहस में हरभजन ने इशारों–इशारों में टीम इंडिया के दिग्गज पूर्व कप्तान एमएस धोनी को भी निशाना बना दिया.

भारत–ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे सिडनी टेस्ट मैच के लिए कप्तान रोहित को प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया था. रोहित को खराब फॉर्म के कारण इस मैच से बाहर किया गया था. हालांकि टीम इंडिया का यही कहना था कि रोहित ने खुद ही टीम के हित में ये फैसला लिया है क्योंकि वो रन नहीं बना पा रहे थे. वहीं मैच के दूसरे दिन शनिवार को रोहित शर्मा ने ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स को एक इंटरव्यू भी दिया और इसमें उन्होंने बताया कि वो टीम को मुश्किल में डालने वालों में से नहीं हैं और हमेशा टीम के भले के हिसाब से सोचते हैं.

'रोहित जैसा कोई कप्तान नहीं'

एक क्रिकेट फैन ने जब रोहित के इंटरव्यू पर सवाल उठाया तो हरभजन ने उसे पर जवाब दिया कि पहले उन्हें रोहित शर्मा का पूरा इंटरव्यू ढंग से सुनना चाहिए. हरभजन ने साथ ही कहा कि रोहित ने जो किया (खुद को ड्रॉप) वो किसी भी भारतीय कप्तान ने विदेशों में कई सीरीज हारने और रन न बनाने के बावजूद भी नहीं किया. हरभजन ने नाम तो नहीं लिया लेकिन ये इशारा एमएस धोनी की ओर था, जो 2011–12 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज हारे थे.

धोनी को बनाया निशाना

इसके बाद एक और यूजर ने रोहित पर सवाल खड़ा किया और कहा कि लीडर बीच मैदान से भागते नहीं हैं. इस यूजर ने धोनी को असली लीडर बताते हुए कहा कि उन्होंने सीनियर खिलाड़ियों को बाहर करने का दम दिखाया था. इस पर हरभजन ने जवाब दिया और लिखा, "मैं जानता हूँ कौन भागा था।याद दिलाऊं? कारण भी बताऊंगा. रोंगटे खड़े हो जाएंगे". एक बार फिर हरभजन ने नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा 2014–14 के ऑस्ट्रेलिया दौरे की ओर था, जिसमें धोनी ने सीरीज के बीच मेलबर्न टेस्ट के बाद संन्यास ले लिया था.

एमएस धोनी के साथ हरभजन के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं और लंबे समय से वो इशारों–इशारों में धोनी को लेकर बयान देते रहे हैं. हालांकि हरभजन ने अपने क्रिकेट करियर का एक बड़ा हिस्सा धोनी के साथ और उनकी कप्तानी में खेलते हुए बिताया. यहां तक कि वो कुछ सीजन पहले तक धोनी की ही कप्तानी में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का भी हिस्सा थे.

मुझे पाकिस्तान छोड़ने की पेशकश की गई थी3 जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान के दावों से हिली शहबाज सरकार

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने बड़ा दावा किया है. पूर्व पीएम ने कहा है कि उन्हें तीन साल के निर्वासन पर देश छोड़ने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था. उन्होंने कहा कि मैंने पेशकश को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा और मरूंगा. खान फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं. पूर्व पीएम के इस दावे ने शहबाज शरीफ सरकार की पोल खोल दी है.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जब मैं अटक जेल में था तो मुझे तीन साल के निर्वासन पर पाकिस्तान को छोड़ने की पेशकश की गई थी, लेकिन मैंने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था क्योंकि मैं पाकिस्तान में ही रहूंगा और यही मरूंगा. जेल में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें इस्लामाबाद में बानी गाल निवास में स्थानांतरित करने के लिए भी परोक्ष रूप से संपर्क किया गया है. खान अगस्त 2023 से अडियाला जेल में कैद हैं.

इमरान बोले– पहले मेरे कार्यकर्ताओं को रिहा किया जाए

पोस्ट में इमरान खान ने कहा कि मेरा रुख साफ है. पहले मेरे उन कार्यकर्ताओं ओर नेताओं को रिहा किया जाए जिन्हें हिरासत में रखा गया है. उसके बाद ही मैं अपनी व्यक्तिगत स्थिति पर चर्चा करने पर विचार करूंगा. पीटीआई चीफ ने कहा कि उनका मानना है कि पाकिस्तान के फैसले देश के भीतर ही लिए जाने चाहिए.

देश की सरकार ने कई कानूनी ढांचों को बाधित किया, बोले इमरान

उन्होंने कहा, हालांकि, जब देश में बुनियादी मानवाधिकारों की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से वैश्विक स्तर पर आवाजें उठेंगी क्योंकि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं इसी उद्देश्य से अस्तित्व में हैं.

दुनियाभर में प्रबुद्ध लोग बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाते हैं. सत्तावादी युग के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन, मौलिक कानूनी अधिकारों का उल्लंघन और संस्थानों के विनाश ने न केवल देश की सामा. जिक और राजनीतिक प्रणालियों को बाधित किया है. बल्कि इसके कानूनी और आर्थिक ढांचे को भी बाधित किया है.

अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ पर आतंकी ग्रहण? कई डेमोक्रेटिक नेताओं ने आने से किया इनकार

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में अब महज 16 दिन बचे हुए हैं. वॉशिंगटन में कड़ी सुरक्षा के बीच शपथ की तैयारियों शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इस बीच अमे. रिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कई डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नेताओं ने ट्रंप के शपथग्रहण न्यौते को अस्वीकार कर दिया है. इसके पीछे किसी अनहोनी की आशंका है.

महज 16 दिन बाद अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल में शपथ लेंगे. शपथ से पहले ही इस पूरे इलाके की जबरदस्त किलेबंदी की गई है. चप्पे–चप्पे पर सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी बड़ी अनहोनी का डर है. डर है कि डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कोई बड़ा हमला हो सकता है. इस बात की आशंका डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टी के नेताओं को है. अमेरिका मीडिया रिपोर्ट्स के मुता. बिक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं.

कई डेमोक्रेटिक नेताओं ने शपथ ग्रहण में जाने से इनकार कर दिया है. वहीं ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के कई सांसदों ने भी चिंता जाहिर की है. अमेरिकी नेताओं में फैले इस डर की वजह नए साल पर हुए आतंकी हमले हैं.

नए साल पर दो जगह आतंकी हमले

नए साल में अमेरिका के न्यू ऑर्लिन्स और लास वेगास में आतंकी हमले हुए थे. न्यू ऑर्लिन्स में एक शख्स ने ट्रक से 50 लोगों को रौंद डाला था. इस लोन वुल्फ अटैक में 15 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं इसके बाद लास वेगास में ट्रंप होटल के सामने मौजूद टेस्ला साइबरट्रक में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ.

अब इन हमलों के बाद अमेरिका में खौफ है. खासकर ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर. दरअसल

अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे. वॉशिंगटन में कड़ी सुरक्षा के बीच शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है. दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के कुछ मंत्रियों ने ट्रंप के शपथ ग्रहण का आमंत्रण भी अस्वीकार कर दिया है. रिपब्लिकन नेताओं ने भी चिंता जाहिर की है.

लास वेगास में जिस टेस्ला साइबरट्रक में ब्लास्ट हुआ था वो ट्रंप होटल के सामने खड़ा था. वहीं अब इसे लेकर जो खुलासा हुआ उसने पेंटागन से वॉशिंगटन तक में खतरे का सायरन बजा दिया है.

डीप स्टेट ड्रोन के जरिए कर सकता है हमला!

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीप स्टेट ड्रोन के जरिए ट्रंप को निशाना बनाने की योजना बना रहा है.

ये खुलासा साइबरट्रक धमाके में मारे गए मैथ्यू लिवेल्स बर्गर ने मौत से पहले किया था. विस्फोट में मारे जाने से पहले उसने 31 जनवरी को चिट्ठी लिखी थी. ये चिट्ठी एक अमेरिकी पत्रकार को लिखी गई थी. जिसमें उसने कहा था कि डीप स्टेट ड्रोन के जरिए ट्रंप को निशाना बनाने की तैयारी में है. इसके कुछ घंटे बाद ही मैथ्यू लिवेल्स बर्गर की साइबरट्रक धमाके में मौत हो गई.

क्या है डीप स्टेट?

इसीलिए माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण वाले दिन भी ट्रंप को निशाना बनाया जा सकता है. लेकिन सवाल है कि मैथ्यू लिवेल्स बर्गर ने चिट्ठी में जिस डीप स्टेट का जिक्र किया वो क्या है.

ड्रैगन की चुप्पी, मरीजों का तांता और श्मशानों में अलर्ट3 आखिर क्यों दुनिया को डरा रहा चीन का नया वायरस?

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

चीन से फिर वैसी की खबर सामने आई है जैसी साल 2019 में कोरोना के समय समय आई थी. चीन में कोरोना जैसे वायरस ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस (एचएमपीवी) से हड़कंप मचा हुआ है. इस नए वायरस के आने से दुनिया पर फिर बड़ा खतरा मंडरा रहा है क्योंकि चीन इस नए खतरनाक वायरस पर चुप्पी साधे हुए हैं. चीन में इस नए वायरस के आने से वहां के कई राज्यों में खतरे का अलर्ट जारी हो गया है. चीन के अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है. मरीज लगातार बढ़ रहे हैं. वायरस के खौफ का आलम ये है कि चीन के श्मशानों को अलर्ट कर दिया गया है. इस वायरस को लेकर भारत में भी एडवाइजरी जारी हो गया है.

इस वायरस का व्यवहार काफी हद तक कोरो. `ना जैसा ही माना जा रहा है. कुछ लोग इसे कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं. पड़ोसी मुल्क को लेकर दावा किया जा रहा है कि कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है. अस्पतालों में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है. सोशल मीडिया पर चीन के कई वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें लोग मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं. दावा किया जा रहा है कि यह वायरस भी कोरोना की तरह हवा से फैल रहा है. खांसने और छींकने से भी वायरस के फैलने का खतरा है.

चीन में कहां–कहां फैला यह वायरस?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस वायरस की चपेट में चीन के कई राज्य आ चुके हैं. यह एक आरएनए वायरस है. इसमें राजधानी बीजिंग का भी नाम शामिल है. चीन के जिन राज्यों में यह वायरस फैला है उसमें बीजिंग के अलावा, तियानजिन, शंघाई, झेजियांग, हेबेई और ग्वांगझू शामिल हैं. इन सभी राज्यों में वायरस

सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों की सच्चाई क्या है. ये चीन के सिवा कोई नहीं जानता है लेकिन चीन में नए वायरस की दस्तक देने की खबर 100 आने सच है और ये भी सच है इस वायरस ने चीन की डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी की सांसें फुल दी हैं. सोशल मीडिया पर वायरल कई वीडियो ऐसे भी हैं जिनमें मरीजों की देखभाल के लिए अस्पताल के कॉरिडोर में भी बेड की व्यवस्था की गई है.

एचएमपीवी वायरस और कोरोना वायरस में समानता

इस एचएमपीवी वायरस को लेकर सबसे ज्यादा डराने वाली बात ये है कि ये वायरस ठीक कोरोना की तरह की हमला कर करता है और ठीक उसी स्टाइल में फैलता है. कोरोना वायरस में शुरुआती लक्षण सर्दी, खांसी और बुखार होते हैं.

एचएमपीवी के मरीजों में भी शुरुआती लक्षण सर्दी, खांसी और बुखार ही देखा जा रहा है. कोरोना वायरस एक से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है. एचएमपीवी भी कोरोना की तरह एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है. कोरोना का सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों और बुजुर्गों पर होता है जबकि एचएमपीवी भी 2 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल से बड़े बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक है.

चीन महज निमोनिया बता रहा

हैरानी की बात है कि चीन इस नए वायरस को लेकर ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया दे रहा है जैसे उसने कोरोना काल के वक्त दी थी तब चीन ने इस वायरस को महज निमोनिया बताया था. अब चीन एचएमपीवी को भी निमोनिया बता रहा है. हालांकि चीन के डिजीज कंट्रोल अथॉरिटी ने इसकी निगरानी के लिए एक पायलट मॉनिटरिंग सिस्टम का गठन किया है. जो इस वायरस पर रिसर्च कर रही है, लेकिन चीन से आई तस्वीरें अगर सच है तो वाकई ये दुनिया के लिए खतरे का अलर्ट है.

जिस सोरोस पर भारत में बवाल, उसे बाइडेन ने दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कुल 19 लोग हुए सम्मानित

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन, फैशन डिजाइनर राल्फ लॉरेन, फुटबॉल सुपरस्टार लियोनल मेस्सी, पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत एश्टन कार्टर और निवेशक जॉर्ज सोरोस के अलावा 14 लोगों को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है. बाइडेन शनिवार दोपहर को अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास और कार्यालय व्हाइट हाउस में पुरस्कार विजेताओं को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया. व्हाइट हाउस ने शनिवार को कहा कि यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है, जिन्होंने अमेरिका की समृद्धि, मूल्यों या सुरक्षा, वैश्विक शांति या अन्य महत्वपूर्ण सामा. जिक, सार्वजनिक या निजी प्रयासों में योगदान दिया है. व्हाइट हाउस ने कहा कि पुरस्कार के लिए चुने गए बिल क्लिंटन, लॉरेन, मेस्सी, कार्टर और सोरोस सहित ये 19 व्यक्ति ऐसे महान नेता हैं, जिन्होंने अमेरिका और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया है.

19 लोगों को मिला सर्वोच्च नागरिक सम्मान

दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 19 लोगों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है. जिसमें पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन, अभिनेता माइकल जे फॉक्स, यू 2 रॉक बैंड फ्रंटमैन बोनो, दिग्गज सेवानिवृत्त बास्केटबॉल खिलाड़ी इरविन मैजिक जॉनसन और अन्य शामिल हैं. समारोह के दौरान जब उनके नाम की घोषणा की गई तो हिलेरी क्लिंटन को उपस्थित लोगों से खड़े होकर तालियां मिलीं.

जॉर्ज सोरोस को भी किया गया सम्मानित

ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक जॉर्ज सोरोस को भी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है. उनके बेटे एलेक्स सोरोस ने उनकी ओर से सम्मान स्वीकार किया. मरणोपरांत पुरस्कार पाने वालों में पूर्व अटॉर्नी जनरल रॉबर्ट फ्रांसिस कैनेडी, पूर्व अमे. रिकी रक्षा सचिव एश्टन बाल्डविन कार्टर, मिसिसिपी फ्रीडम डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक फैनी लू हैमर और मिशिगन के पूर्व गवर्नर जॉर्ज रोमनी शामिल हैं.

इन लोगों को भी मिल सम्मान

अन्य लोगों में स्पेनिश–अमेरिकी पाक कला के अन्वेषक जोस एंड्रेस, उद्यमी टिम गिल, जेन गुडाल, फैशन डिजाइनर राल्फ लॉरेन, वोग के एडिटर एना विंटोर, द कार्लाइल ग्रुप के सह–संस्थापक डेविड रुबेनस्टीन, विज्ञान शिक्षक विलियम सैनफोर्ड नाई, पुरस्कार विजेता लेखक, निर्देशक, लेखक और नाटककार जॉर्ज स्टीवंस जूनियर, अभिनेता, निर्देशक और निर्माता एना विंटोर शामिल हैं.

फुटबॉलर मेसी का नाम लिस्ट से बाहर पुरस्कार पाने वालों में अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी का भी नाम था. हालांकि, शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण वह इसमें शामिल नहीं हो सके, सीबीएस न्यूज ने व्हाइट हाउस का हवाला देते हुए बताया. बाइडेन ने पुरस्कार देने से पहले अमेरिका की मदद करने के उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद दिया.

बाइडेन ने दिया धन्यवाद

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में अंतिम बार, मुझे वास्तव में असाधारण लोगों के एक समूह को हमारे देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने का सम्मान मिला है, जिन्होंने अमेरिका की संस्कृति और उद्देश्य को आकार देने के लिए अपना प्रयास किया है, इसलिए मैं आप सभी को बस इतना कहना चाहता हूं कि इस देश की मदद करने के लिए आपने जो कुछ भी किया है।

कर्नाटक में अतुल सुभाष जैसा केस... पत्नी के झगड़े से तंग आकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने की आत्महत्या

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

कर्नाटक में एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पत्नी से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. उसने नदी में कूदकर खुदखुशी कर ली. अतुल सुभाष सुसाइड केस के बाद इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां घरेलू हिंसा से तंग आकर पति ने जान दे दी.

कर्नाटक से एक और अतुल सुभाष जैसा केस सामने आया है, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रमोद ने अपनी पत्नी के लड़ाई–झगड़ों से तंग आकर आत्महत्या कर ली. उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी. बताया जा रहा है कि प्रमोद 29 दिसंबर को घर से बाहर गया था और इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. तब से ही वह गायब था. फिर उसका शव मिला.

जब 29 दिसंबर को प्रमोद घर से निकला, तो वह अपना फोन भी घर पर छोड़ गया था. लंबे समय तक जब प्रमोद वापस नहीं लौटा तो माता–पिता ने पुलिस को जानकारी दी और तलाश शुरू की गई. तलाश में हेमावती नदी के पुल के पास से प्रमोद की बाइक और बैंक पास. बुक बरामद हुई. इसके बाद बैंक पासबुक पर लिखे नंबर पर संपर्क किया गया, जिसे प्रमोद के पिता ने उठाया. पुलिस ने उन्हें जब बाइक के बारे में जानकारी दी तो प्रमोद की पहचान हो गई. पहचान होने के बाद प्रमोद के शव को नदी से खोजकर बाहर निकाला गया.

पत्नी के लड़ाई–झगड़े से था परेशान

प्रमोद बेंगलुरु में बेंज कंपनी में काम करता था. वह अपनी पत्नी के साथ होने वाले लड़ाई–झगड़े से तनाव में आ गया था. इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रमोद को उसके भाई–बहन भी परेशान कर रहे थे. इस सब से छुटकारा पाने के लिए प्रमोद ने मौत को गले लगा लिया और नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली. जब प्रमोद का शव बरामद कर लिया गया, तो परिजन मौके पर पहुंच गए. प्रमोद की पत्नी भी अपनी मां और बच्चों के साथ प्रमोद के शव को देखने आई.

पति–पत्नी के परिवार वालों में विवाद

इसी दौरान पत्नी के परिजनों और प्रमोद के परिजनों के बीच विवाद हो गया, जहां भीड़ को काबू करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

सीआईएसएफ की पहल से आत्महत्याओं में 40: की कमी, राष्ट्रीय औसत से नीचे पहुंचा मृत्यु दर

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

सीआईएसएफ का आत्महत्या दर 2024 में राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गया है. इन प्रयासों से जवानों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्य-जीवन संतुलन में सुधार हुआ है. सीआईएसएफ ने जवानों के तनाव को कम करने के लिए प्रोजेक्ट ३मन३ और नई पोस्टिंग नीति समेत कई विशेष कदम उठाए हैं.

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपने जवानों की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं. इसमें कई तरह के एक्स्ट्रा एक्टिविटी जैसे डेली 'ब्रिफिंग–डीब्रिफिंग' सत्रों का आयोजन, प्रोजेक्ट 'मन' शामिल है. इन प्रयासों का असर यह हुआ है कि 2024 में सीआईएसएफ के आत्महत्या के मामलों में 40: की कमी दर्ज की गई है.

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में देश की औसत आत्महत्या दर प्रति लाख 12.4 थी. 2024 में, सीआईएसएफ ने अपनी आत्महत्या दर को घटाकर प्रति लाख 9.87 कर दिया, जो पिछले पांच सालों में पहली बार राष्ट्रीय औसत से नीचे है. सीआईएसएफ ने जवानों के तनाव को कम करने के लिए नई पोस्टिंग नीति कई मायनों में सराहनीय कदम हैं.

तनाव कम करने के लिए विशेष कदमरू

सीधा संवाद : कमांडिंग अधिकारी नियमित रूप से जवानों के साथ सीधे बातचीत करते हैं. "अपने जवानों को जानें और उनकी बातें सुनें" जैसे प्रयासों से तनाव के शुरुआती संकेतों को पहचाना जा रहा है. रोजाना होने वाले "ब्रिफिंग–डीब्रिफिंग" सत्रों में जवानों की समस्याओं पर तुरंत ध्यान दिया जा रहा है.

योग और खेलकूद : हर यूनिट में प्रशिक्षित योग प्रशिक्षकों की मदद से नियमित योग कक्षाएं चल रही हैं. जवानों और अधिकारियों के लिए रोजाना एक घंटे का खेल सत्र आयोजित किया जा रहा है.

ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली : जवानों की शिकायतों को जल्दी सुलझाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, जो डीजी स्तर तक निगरानी सुनिश्चित करता है.

प्रोजेक्ट "मन": 24×7 टेली–काउंसलिंग और व्यक्तिगत काउंसलिंग के जरिए जवानों को मानसिक स्वास्थ्य सहायता दी जा रही है. अब तक 4200 से अधिक जवानों ने इस सेवा का लाभ उठाया है.

मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन : एम्स, नई दिल्ली के सहयोग से एक व्यापक मानसिक स्वास्थ्य अध्ययन किया गया. इसकी सिफारिशें यूनिट स्तर पर लागू की जा रही हैं.

नई पोस्टिंग नीति : दिसंबर 2024 में एक नई एचआर नीति लागू की गई, जिसमें पोस्टिंग के लिए जवानों की पसंद को प्राथमिकता दी गई है. यह नीति महिला जवानों, विवाहित जोड़ों और रिटायरमेंट के करीब पहुंच रहे कर्मियों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखती है. सीआईएसएफ का आत्महत्या दर 2024 में राष्ट्रीय औसत से नीचे आ गया है. इन प्रयासों से जवानों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्य–जीवन संतुलन में सुधार हुआ है.

दिल्ली में फर्जी वोटरः अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल पर बोला हमला, कहा- आप चुपचाप खेल कर रही

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में फर्जी वोटर के मामले में आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है. उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए कहा कि एक ही घर पर सैकड़ों वोट बन जाते हैं, मकान मालिक को पता नहीं चलता है. आम आदमी पार्टी चुपच. ाप खेल रही है. इस खुलासे की जड़ तक जाना चाहिए, जो इसके पीछे है उनको दंडित करना चाहिए.

दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले फर्जी वोटर को लेकर भाजपा और आप ने एक–दूसरे के खिलाफ हमला तेज कर दिया है. भाजपा ने आरोप लगाया कि आप सत्ता में बने रहने के लिए मतदाता धोखाधड़ी का सहारा ले रही है. इस बीच, पार्टी ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पोस्टर जारी किया है. इसमें कहा गया है कि 40 से 80 वर्ष की आयु के कई फर्जी वोटर बिना मकान मालिक की अनुमति के बनाये गए हैं. वहीं, बीजेपी ने इसे लेकर केजरीवाल पर हमला बोलते हुए उस पर आरोप लगाया कि सत्ता में रहने के लिए फर्जीवाड़ा का सहारा ले रही है.

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने इसे लेकर आप पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि मैं ज्ट9 भारतवर्ष को बधाई देता हूं, लो. कतंत्र को बचाने का काम किया. उन लोगों ने फर्जी वोट बनाने का काम किया, क्योंकि दस साल से ये दिल्ली में कुछ नही कर सके.

आम आदमी चुपचाप खेल कर रहीः अनुराग

उन्होंने कहा कि एक ही घर पर सैकड़ों वोट बन जाते हैं, मकान मालिक को पता नहीं चलता है. आम आदमी पार्टी चुपचाप खेल रही है. इस खुलासे की जड़ तक जाना चाहिए, जो इसके पीछे है उनको दंडित करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि ये रोहिंग्या/बांग्लादेशी मुस्लिम को संरक्षण देते आ रहे हैं, जो 18000 रुपए केजरीवाल (मौलवी) देते थे, क्या वो घुसपैठ करके आए लोगों का ध्यान रखने के लिए देते थे.

उन्होंने कहा कि जनता के सामने केजरीवाल का रोहिंग्या/बांग्लादेशी को लेकर प्रेम सामने आ गया है. जो जरूरी कदम है वो दिल्ली बीजेपी उठा रही है.

बीजेपी सरकार बॉर्डर की सुरक्षा करने में नाकामरू केजरीवाल

दूसरी ओर, केजरीवाल ने कहा कि इस से तो लगता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ करवा रही है. क्या केंद्र सरकार बांग्लादेश बॉर्डर से जानबूझकर घुसपैठ करवा रही है या बीजेपी सरकार बॉर्डर की सुरक्षा करने में नाकाम है?

उन्होंने बीजेपी पर इसे लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया. दूसरी ओर, फर्जी वोटर्स को लेकर ज्ट9 भारतवर्ष द्वारा पूछे गए सवाल पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि साउथ दिल्ली में अभी तक 5 बांग्लादेशियों से फर्जी वोटर कार्ड बरामद हुए थे, लेकिन ये फ्रेश बनाए गए थे, जिनका अभी तक वोटिंग में इस्तेमाल नहीं हुआ है, बाकी जांच की जा रही है. इस से तो लगता है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जानबूझकर बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ करवा रही है।

उन्होंने कहा कि अभी तक की जांच में बांग्लादेशियों को भारत में या फिर कहे दिल्ली में बसाने वाले किसी भी सिंडिकेट का कोई भी राजनेतिक लिंक नहीं मिला है. बता दें कि बीज. ेपी और आप पार्टी एक–दूसरे पर आरोप लगा रही है.

एसटीएफ में दम है तो मेरे सीने पर गोली मारे... योगी सरकार में मंत्री आशीष पटेल ने खोला मोर्चा

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल एसटीएफ को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं. अब उन्होंने कहा कि तुम पैर पर गोली मारते हो, अगर दम है तो मेरे सीने पर गोली मारो. आपके पास तंत्र है और मेरे पास जनतंत्र है. जब जनतंत्र साथ है तो तंत्र से कोई डरने की जरूरत नहीं है.

यूपी सरकार में मंत्री आशीष पटेल पर तकनीकी शिक्षा विभाग में लेक्चरर्स के प्रमोशन में अनियमितताओं के आरा. ेप लग रहे हैं. ये आरोप सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने लगाया है. गुरुवार को आशीष ने पल्लवी पटेल के साथ ही एसटीएफ पर भी हमला बोला. एसटीएफ के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्होंने कहा कि तुम पैर पर गोली मारते हो, अगर दम है तो मेरे सीने पर गोली मारो. मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं. मेरी गलती है कि मैंने वंचित वर्ग को आगे बढ़ाया. ऐसी गलती मैं करता रहूंगा. डरूंगा नहीं, आपके पास तंत्र है और मेरे पास जनतंत्र है. जब जनतंत्र साथ है तो तंत्र से कोई डरने की जरूरत नहीं है.

आशीष पटेल ने कहा, मैं एसटीएफ के उन अधिकारियों के बारे में जानना चाहता हूं कि जिस विधानसभा में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, उसी विधानसभा में दो लोगों को धरना देने के लिए छोड़ दिया. आज एसटीएफ को मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा नाम स्पेशल टास्क फोर्स है. मेरा नाम आशीष पटेल है. एसटीएफ को कहना चाहता हूं कि तुम पैर में गोली मारते हो ना, आओ सीने में गोली मारो.

पल्लवी पटेल को बताया धरना मास्टर

मंत्री ने आगे कहा, आप डरा करके 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले को दबा नहीं सकते. मेरी राष्ट्रीय अध्यक्ष को केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से पैक कर रखा है. उनके पास केंद्र सरकार की सुरक्षा है पर मैं तो आपके भरोसे हूं. आशीष ने पल्लवी पटेल को लेकर कहा कि सरकार की एक धरना मास्टर हैं. उनको प्रायोजित किया जाता है. उनको जब भी मौका मिलता है तो उनको धरने पर बैठा दिया जाता है.

मंत्री आशीष पटेल ने आगे कहा, मैं शिशिर बाबू से कहना चाहता हूं कि आप खबरें छपवाना बंद कर दीजिए. अभी मैं मर्यादा में हूं. अगर आप मर्यादा पार करेंगे तो मैं भी मर्यादा भूल जाऊंगा. एसटीएफ का वो कौन सा अधिकारी है कि जहां सिर्फ विधायक जा सकता है, वहां दो लोगों को और धरने के लिए भेजा जा रहा है.

षड्यंत्रों की रचयिता है एसटीएफ

आशीष पटेल ने कहा, पिछले कुछ दिनों से मैं मीडिया में ज्यादा छप रहा हूं. मेरा सकारात्मक छिपाकर नकारात्मक पक्ष दिखाया जाता है. अब और ताकत से लड़ूंगा. मैं षड्यंत्रों से डरने वाला नहीं. सीबीआई से मेरी जांच कराइए. सूचना विभाग का दुरुपयोग करके मेरी मान मर्यादा मत खराब करिए, नहीं तो ईंट जवाब पत्थर से दूंगा.

आशीष पटेल ने कहा, 14 में से 7 इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने पिछड़े वर्ग के डायरेक्टर बनाए. अगर यही मेरी गलती है तो ऐसी गलती में करता रहूंगा. अगर आपके पास तंत्र है तो मेरे पास जनतंत्र है. उन्होंने कहा कि एसटीएफ से सावधान रहिएगा, सारे षड्यंत्र की रचयिता यही है.

अनुप्रिया पटेल ने क्या कहा?

अनुप्रिया पटेल ने कहा, मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है. बात प्रतिष्ठा पर आएगी तो हम समझौता नहीं करेंगे.

पिछले दिनों जो बात सामने आई, वो हम जानते हैं कि किसके इशारे पर ये सब किया गया है.

सरकार आगे आए, कौन रोक रहा? चिन्मय दास की जमानत खारिज होने पर भड़के टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

बांग्लादेश में चिन्मय दास की जमानत याचिका खारिज होने के बाद से ही लोग निराश हैं, इसके अलावा बांग्लादेश को लेकर नाराजगी भी सामने आ रही है. टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है, उन्होंने कहा कि भारत सरकार को किसने रोका है. उन्हें इस बारे में कोई कदम उठाना चाहिए.

बांग्लादेश की जेल में बंद इस्कॉन के पूर्व नेता चिन्मय दास की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. वे पिछले 42 दिनों से जेल में बंद हैं. ये दूसरी बार है जब कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की है. कोर्ट की तरफ से याचिका खारिज होने पर कई लोगों की नारा. जगी भी सामने आ रही है.

इस मामले पर अब टीएमसी महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भारत सरकार को इस मामले को लेकर आगे आना चाहिए, और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ मिलकर उठाना होगा. उन्होंने कहा कि यह मेरे विशेषाधिकार या जनादेश के तहत नहीं है. अंत. रराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी इसे लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सामने सख्ती से उठाना चाहिए. यह मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन है.

अभिषेक बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को कौन रोक रहा है? उन्हें इस मामले पर बात करनी चाहिए. हमारी पार्टी के नजरिये से हमने पहले दिन से ही अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है. केंद्र सरकार जो भी कदम उठाएगी दृ एक पार्टी के तौर पर टीएमसी हर भारतीय की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार का पूरा समर्थन करेगी. उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि वे उन लोगों को जवाब दें जो हमें प्रताड़ित कर रहे हैं और हमें ही आंख दिखा रहे हैं.

अभिषेक बनर्जी ने बांग्लादेश के मुद्दे केंद्र सरकार से जवाब देने की बात कही है. चिन्मय दास के वकील बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती हैं, यही कारण है कि उनकी तरफ से अन्य वकीलों ने सुनवाई में भाग लिया.

सुप्रीम कोर्ट के 11 वकील चिन्मय कृष्ण दास की जमानत की सुनवाई का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए थे.

बीजेपी सांसद महेश शर्मा की सदस्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि आखिर इस मामले में डीएम नोएडा का नाम हटाने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों दिया? वकील जब जवाब नहीं दे पाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है.

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

गौतमबुद्धनगर के भाजपा सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने डॉ. महेश शर्मा, चुनाव आयोग समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ता गीतारानी शर्मा के वकील से पूछा कि याचिका से डीएम का नाम हटाने का आद. `श इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों दिया था? हालांकि वकील ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, जिसके बाद बेंच ने सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया.

सुप्रीम कोर्ट 24 मार्च के बाद गए गीतारानी याचिका पर अगली सुनवाई करेगा. यह याचिका बुलंदशहर की रहने वाली चुनावी उम्मीदवार गीतारानी शर्मा की है, जिनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी और अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवा. जा खटखटाया है.

याचिका में पीठासीन अधिक. ारी पर गलत तरीके से उनका नामांकन निरस्त करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. याद रहे कि हाईकोर्ट ने कहा था कि विपक्षी सांसद अपना जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करते हैं तब हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई के आदेश देगा.

इसके बाद हाई कोर्ट ने केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त की आपत्ति को स्वीकारते हुए निर्वाचन आयुक्त को पक्षकार से हटा दिया था. साथ ही डीएम गौतमबुद्धनगर और विपक्षी चार व पांच को भी पक्षकार से हटाने का आदेश दिया था.

गीतारानी शर्मा ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए निर्दलीय पर्चा दाखिल किया था, लेकिन उनका पर्चा खारिज कर दिया गया था. गीतारानी 2022 में भी विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं. उनके मुताबिक राजनीति में आने के लिए उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी.

तीसरी बार सांसद चुने गए हैं महेश शर्मा

महेश शर्मा तीसरी बार गौतमबुद्धनगर सीट से सांसद चुने गए हैं. 2024 के चुनाव में शर्मा ने सपा के महेंद्र नागर को हराया था. 2014 में शर्मा पहली बार इस सीट से जीतकर संसद पहुंचे थे. शर्मा केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं.

2008 में गौतमबुद्धनगर सीट सियासी तौर पर अस्तित्व में आया. गौतमबुद्धनगर लोकसभा के अधीन नोएडा, खुर्जा, दादरी, जेवर और शिकंदराबाद की विधानसभा सीटें हैं.

'जीकर भी क्या करोगी, अगर मुझे३', मां और 4 बहनों की हत्या से पहले ऐसा क्यों बोला था अरशद?

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

लखनऊ के बहुचर्चित सामूहिक हत्याकांड में फिर से नए खुलासे हुए हैं. आरोपी अरशद ने पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें बताई हैं. हत्याकांड से ठीक पहले उसने क्या-क्या किया, इस बारे में अरशद ने जो कुछ भी बताया वो बेहद हैरान करने वाला है.

लखनऊ के शरणजीत होटल में मां और 4 बहनों की हत्या करने वाले अरशद को लेकर फिर नए खुलासे हुए हैं. अरशद ने जबरदस्ती अपनी मां और बहनों को शराब पिलाई थी. ताकि उन्हें मारने में कोई परेशानी न हो. पिता से कहकर उसने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई. उसमें शराब मिलाकर दी. कहा कि इसे पी लो. महिलाओं ने इसका विरोध किया तो बोला– जीकर क्या करोगी, अगर मुझे ही उन्होंने मार डाला तो. अरशद ने पुलिस को बताया था कि उसे डर था कि मोहल्ले वाले उसकी हत्या कर देंगे. उसे मारने के बाद उसकी बहनों का सौदा कर दिया जाएगा. अरशद ने कहा– मैंने तो बहनों की इज्जत बचाने की खातिर उन्हें मारा है.

पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि अरशद हमेशा से शराब पीने का आदी है. वह शराब पीकर घरवालों के साथ मारपीट किया करता था। 31 दिसंबर की रात उसने चारबाग में शराब खरीद कर पी और अपने साथ एक बोतल होटल ले आया. होटल में मां और बहनों को धमका कर शराब पिलाई, जिससे वे उल्टियां करने लगीं. वारदात के बाद जब पुलिस कमरा नंबर 109 में पहुंची तो पूरे कमरे और बिस्तर पर उल्टी पड़ी थी.

अरशद ने पुलिस को बताया कि उसने मां–बहनों को धमकाया था कि अगर मोहल्ले वालों ने उसे मार दिया तो वो सब जीकर क्या करेंगी? इसके बाद उसने पिता को बाहर भेज कर कोल्डड्रिंक मंगवाई. उसमें मिलाकर शराब पिलाई थी. कमरे से शराब और कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी मिली हैं.

दुपट्टे से घोंटा गला, कलाई काटी

अरशद ने पुलिस को बताया कि शराब पिलाने के बाद खाने में उन्हें नशीली गोलियां भी दीं. उसके बाद दुपट्टे और रुमाल सभी के मुंह में ठूंस दिए, जिससे आवाज बाहर न जा सके. बेसुध होने के बाद पिता बदर ने बहनों के हाथ की नस सर्जिकल और सामान्य ब्लेड से बारी–बारी काटी. चारों के हाथ से खून निकल रहा था. इसके बाद आस्मा समेत सभी के गले में दुपट्टे का फंदा कसकर मार डाला. गला कसते समय अरशद और बदर ने दुपट्टे का एक–एक सिरा पकड़ा था. जब तक पांचों का दम नहीं निकला तब तक दोनों गला कसते रहे.

वीडियो में पांचों लाश भी दिखाईं

वारदात को अंजाम देने के बाद अरशद ने होटल के उसी कमरे से एक वीडियो बनाया. वीडियो में बेड पर पड़े बहन और मां के शव भी दिखाए. वीडियो में अरशद ने कहा, 'मैंने अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए उन्हें मारा. हमारे घर में जो सामान था उसे अनाथ आश्रम में दान कर दिया जाए. मैं नहीं देख सकता था कि मेरी बहनों को हैदराबाद में बेच दिया जाए.' उसने बस्ती के लोगों पर जमीन हड़पने और उत्पीड़न का आरोप भी लगाया।

क्राइम थ्रिलर फिल्में देखने का शौकीन

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस की पूछताछ में यह भी पता चला है कि अरशद क्राइम थ्रिलर सीरियल देखने का शौकीन था. उसने दृश्यम फिल्म करीब 10 बार देखी थी.

बेंगलुरु शहर, 20 दिन और दो इंजीनियर... अतुल-प्रमोद का एक सा दर्द, हल भी एक- सुसाइड; कचोट कर रख देगी दोनों कहानियां

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

अतुल सुभाष केस के ठीक 20 दिन बाद एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पत्नी से परेशान होकर खुदकुशी कर ली. मृतक का नाम प्रमोद था. प्रमोद और अतुल के केस पर गौर करें तो दोनों की कहानी हूबहू एक सी थी. चलिए डालते हैं दोनों की केस पर एक नजर...

कर्नाटक के बेंगलुरु में अतुल सुभाष सुसाइड केस का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि उन्हीं की तरह एक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली. जैसे अतुल सुभाष ने आत्महत्या के लिए पत्नी और ससुराल वालों को दोषी ठहराया था. ठीक उसी तरह प्रमोद की बीवी पर भी उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगा. दोनों ही कहानियां हूबहू एक सी हैं.

अतुल और प्रमोद दोनों ही पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे. अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे. लेकिन कमी थी तो बस सकून की. दोनों ही अपनी–अपनी पत्नियों से परेशान थे. अतुल ने 9 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित अपने फ्लैट में फंदा लगाकर जान दे दी. मरने से पहले 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा साथ ही एक वीडियो भी बनाया. वहीं, प्रमोद घर से बहाना बनाकर निकला. फिर वापस ही नहीं लौटा. प्रमोद के माता–पिता ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई. उसके बाद जाकर प्रमोद का शव नदी से बरामद हुआ.

बात करें, अतुल केस की तो इसमें पत्नी निकिता, सास निशा और साले की गिरफ्तारी हो चुकी है. सभी आरा. `पी न्यायिक हिरासत में हैं. मामला बेंगलुरु की लोअर कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. उधर, प्रमोद के केस में पुलिस अभी जांच कर रही है. इस केस में फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है.

अतुल ने मरने से पहले कहा था– मुझे मेरी बीवी और ससुरालियों ने मरने के लिए विवश किया है. मेरे ऊपर 9 से ज्यादा झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं. मेरे बेटे से भी मुझे मिलने नहीं दिया जाता. इसलिए मैं परेशान होकर जान दे रहा हूं.

दूसरे केस की बात करें तो, प्रमोद 29 दिसंबर को घर से बाहर गया था और इसके बाद वह वापस नहीं लौटा. तब से ही वह गायब था. फिर उसका शव मिला. जब 29 दिसंबर को प्रमोद घर से निकला, तो वह अपना फोन भी घर पर छोड़ गया था. लंबे समय तक जब प्रमोद वापस नहीं लौटा तो माता–पिता ने पुलिस को जानकारी दी और तलाश शुरू की गई. तलाश में हेमावती नदी के पुल के पास से प्रमोद की बाइक और बैंक पासबुक बरामद हुई. इसके बाद बैंक पासबुक पर लिखे नंबर पर संपर्क किया गया, जिसे प्रमोद के पिता ने उठाया. पुलिस ने उन्हें जब बाइक के बारे में जानकारी दी तो प्रमोद की पहचान हो गई. पहचान होने के बाद प्रमोद के शव को नदी से खोजकर बाहर निकाला गया.

पत्नी के लड़ाई–झगड़े से था परेशान

प्रमोद बेंगलुरु में बेंज कंपनी में काम करता था. वह अपनी पत्नी के साथ होने वाले लड़ाई–झगड़े से तनाव में आ गया था. इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि प्रमोद को उसके भाई–बहन भी परेशान कर रहे थे.

इस सब से छुटकारा पाने के लिए प्रमोद ने मौत को गले लगा लिया और नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली. जब प्रमोद का शव बरामद कर लिया गया, तो परिजन मौके पर पहुंच गए.

प्रमोद की पत्नी भी अपनी मां और बच्चों के साथ प्रमोद के शव को देखने आई.

इसी दौरान पत्नी के परिजनों और प्रमोद के परिजनों के बीच विवाद हो गया, जहां भीड़ को काबू करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.

रूस का गैस अब यूक्रेन के रास्ते यूरोप नहीं जा पाएगा, तो क्या यूरोप संकट में आ जाएगा?

1 जनवरी 2025 से यूक्रेन के जरिए यूरोप को रूसी गैस की सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है. 2019 में हुआ पांच साल का ट्रांजिट समझौता खत्म होने की वजह से ऐसा हुआ है. हालांकि यूरोपीय कमीशन ने कहा है अगर रूस ने गैस सप्लाई बंद कर दी, तो कोई टेंशन नहीं है. उसके पास बैकअप प्लान तैयार है.

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

1 जनवरी 2025 से यूरोप में एक ऐतिहासिक बदलाव आया है. दरअसल यूक्रेन के रास्ते से होने वाली गैस सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है. यह घटना रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच हुई है, जिसे 2025 में तीन साल हो जाएंगे. इस एक बदलाव का असर यूरोप के ऊर्जा संकट पर गहरा पड़ सकता है.

दशकों तक यह पाइपलाइन, जो रूस से गैस को यूक्रेन के रास्ते यूरोप तक पहुंचाती थी, ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी निर्भरता का प्रतीक मानी जाती थी. लेकिन अब इस पाइपलाइन का बंद होना रूस, यूक्रेन और यूरोपीय संघ के रिश्तों में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है, जो ऊर्जा नीतियों, राजनीतिक खींचतान और भविष्य की रणनीतियों को प्रभावित करेगा. आइए जानते हैं इसका इतिहास और यूरोप इस से निपटने के लिए कितना तैयार है?

समझौते का अंत और पाइपलाइन का बंद होना कई दशकों तक, यूरोप रूसी गैस पर निर्भर रहा, जो यूक्रेन के माध्यम से यूरोपीय देशों तक पहुंचती थी.

इस रास्ते ने यूरोप की गैस जरूरतों का लगभग 35: हिस्सा पूरा किया था, जिससे रूस को अरबों डॉलर की आय हुई और यूक्रेन को ट्रांजिट शुल्क के रूप में आर्थिक लाभ मिला. लेकिन फिर 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद से रिश्तों में तनाव की शुरुआत हुई. इसके बाद 2022 के फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो यूरोप में रूस की आपूर्ति में गिरावट आई है जिसने यूरोपीय संघ को रूसी गैस पर अपनी निर्भरता में कटौती करने के लिए प्रेरित किया. मॉस्को ने अपनी यूरा. `पीय गैस बाजार हिस्सेदारी बनाने में आधी शताब्दी बिताई, जो अपने चरम पर लगभग 35: थी लेकिन गिरकर लगभग 8: हो गई है. 2019 में रूस और यूक्रेन के बीच पांच साल का गैस ट्रांजिट समझौता समाप्त हो गया था, और यूक्रेन ने इसे आगे बढ़ाने से मना कर दिया. 31 दिसंबर 2024 को यूक्रेनी गैस ट्रांजिट ऑपरेटर ने यह घोषणा की कि 1 जनवरी 2025 के लिए कोई गैस फ्लो का अनुरोध नहीं किया गया.

इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के रास्ते से गैस की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है.

यूरोप बैकअप प्लान क्या है?

जब 2 साल पहले रूस–यूक्रेन शुरु हुआ तो इसके बावजूद यूरोप ने रूस से गैस खरीदना जारी रखा, जिस पर उसे आलोचना भी झेलनी पड़ी. इसके बाद यूरोपीय संघ ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कई वैकल्पिक उपाय अपनाए.

यूरोपीय आयोग ने ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, विस्तार और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को लचीला बनाने की दिशा में कदम उठाए.

यूरोपीय कमीशन ने कहा है अगर रूस ने गैस सप्लाई बंद कर दी, तो कोई टेंशन नहीं है. रूस से आने वाली गैस की कमी को पूरी तरह से लिक्वीफाइड नेचुरल गैस और दूसरे देशों से पाइपलाइन के जरिए गैस आयात करके पूरा किया जा सकता है.

कतर और अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस के आयात को बढ़ाया गया, साथ ही नॉर्वे से पाइप्ड गैस की आपूर्ति में भी इजाफा किया गया.

साल दर साल तूफान की संख्या नहीं बढ़ रही, फिर तबाही इतनी क्यों आ रही?

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती पर तूफानों की संख्या में तो कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन उनके क्रूर रूप में एक बड़ा बदलाव आया है। अब ये तूफान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी हो गए हैं।

वैज्ञानिकों के मुताबिक समुद्रों का तापमान बढ़ने के साथ, तूफानों की ताकत भी नई ऊँचाइयों पर पहुँच गई है. तेज़ हवाएँ, भारी बारिश और भयंकर बाढ़कृये सब मिलकर उन इलाकों में तबाही मचाने लगे हैं, जो पहले ऐसे तूफानों से सुरक्षित माने जाते थे. इसका मतलब ये है कि समुद्री और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लाखों लोग अब कहीं ज्यादा खतरे में हैं. आइए जानते हैं कि आखिर क्यों तूफानों की तीव्रता बढ़ती जा रही है?

क्यों बढ़ रही है तूफानों की तीव्रता?

चक्रवातों की तीव्रता बढ़ने का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है. समुद्र का तापमान बढ़ने से हवा और पानी में ज्यादा ऊर्जा मिलती है, जिससे तूफान अधिक शक्तिशाली बनते हैं. जैसे–जैसे महासागरीय तापमान बढ़ता है, वायुमंडल में ज्यादा नमी और गर्म हवा भी जमा होती है, जो चक्रवातों को तेज़ बना देती है. इन उच्च तापमानों के कारण हवाओं की गति और दबाव में बदलाव आता है, जो चक्रवातों की विनाशक क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है.

30 वर्षों में तूफान हो गए विनाशकारी

1980 से अब तक, हर साल औसतन 47 चक्रवात होते हैं, जिन्हें हरिकेन और तूफान भी कहा जाता है. यह आंकड़े विश्व मौसम विज्ञान संगठन की तरफ से मान्यता प्राप्त डेटा एजेंसियों और अमेरिकी महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन की ओर से संकलित किए गए हैं. हालाँकि चक्रवातों की वार्षिक संख्या में कोई बड़ी परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन उनकी तीव्रता में पिछले 30 वर्षों के दौरान बढ़ोतरी देखी गई है. 1981 से 2010 तक के मुकाबले पिछले दशक में इनकी औसत अधिकतम पवन गति 182 किमी प्रति घंटा से बढ़कर 192 किमी प्रति घंटा (113 से 119 मील प्रति घंटा) हो गई है, जो पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी है.

चक्रवात की गति भी तेज होती जा रही

चक्रवात ऐसे घुमते हुए हवाएं हैं जो कम दबाव वाले क्षेत्र के चारों ओर घूमती हैं और जिनकी गति कम से कम 118 किमी प्रति घंटा होती है. 1981 से 2010 तक, लगभग हर 10 में से एक चक्रवात 250 किमी प्रति घंटा की गति से ज्यादा था, लेकिन पिछले दशक में यह आंकड़ा बढ़कर 1.4 चक्रवातों में से एक हो गया है. यानी कि सबसे विनाशकारी, श्रेणी पांच के तूफानों की संख्या में 40 प्रतिशत का इजाफा हुआ है.

यह आंकड़े संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल के निष्कर्षों पर भी मुहर लगाते हैं जो कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण श्रेणी चार और पांच के तूफानों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है.

‘खोखली है पुतिन की परमाणु धमकी...’ अमेरिका के पूर्व एनएसए ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

अमेरिका के पूर्व अटॉर्नी और संयुक्त राष्ट्र में राजदूत की भूमिका निभा चुके जॉन रॉबर्ट बोल्टन ने टीवी9 भारतवर्ष के साथ खास बात. चीत में हिस्सा लिया. 2018 से 2019 तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर काम करने वाले पूर्व छे। जॉन बोल्टन ने कई मुद्दों पर बेबाक राय रखी. उन्होंने बताया कि अमेरिका की आगामी ट्रंप सरकार के शुरुआती 100 दिन किस तरह के रहने वाले हैं.

बोल्टन ने रूस–यूक्रेन युद्ध रुकवाने को लेकर ट्रंप के दावे और पुतिन की न्यूक्लियर धमकी के साथ–साथ भारत और अमेरिका के संबंधों, एच1बी वीज़ा रिफॉर्म समेत कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की. टीवी9 भारतवर्ष के साथ उनकी बात. चीत का महत्वपूर्ण अंश पढ़िए.

कैसा होगा ट्रंप का दूसरा कार्यकाल?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल कैसा रहेगा? खासतौर पर शुरुआती 100 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या उनका दूसरा कार्यकाल पहले कार्यकाल से काफी अलग होगा? जानिए ट्रंप के पूर्व सहयोगी ने इस सवाल का क्या जवाब दिया?

राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप काफी एक्टिव दिखेंगे, उन्होंने कई महत्वपूर्ण एजेंडा रखा है. उन्हें अमेरिका की घरेलू अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर काफी काम करना है. जो कि हमेशा से उनकी प्राथमिकता रहे हैं. जैसे– अवैध अप्रवासियों को बाहर करना, जिसका उन्होंने शपथ ग्रहण के साथ ही वादा किया है.

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल पहले कार्यकाल की तरह ही होगा, यानी यह इस समय व्यवस्थित लग सकता है और शुरुआत में व्यवस्थित हो भी सकता है, लेकिन यह बहुत अधिक अव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेगा.

बोल्टन ने कहा कि ट्रंप की सोच पूरी तरह से लेन–देन वाली है और वह हर चीज को राजनी. तिक तौर पर मिलने वाले फायदे के नजरिए से देखते हैं. इसलिए ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भी पहले की तरह होगा लेकिन इस बार दुनिया राजनीतिक और आर्थिक तौर पर अधिक खतरनाक स्थिति में है. लिहाज़ा ट्रंप जिन मुद्दा. ` को लेकर बात कर रहे हैं उनमें से बहुत–सी चीजों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं.

रूस–यूक्रेन युद्ध कैसे खत्म करवाएंगे ट्रंप?

चुनाव जीतने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे में रूस–यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने का वादा किया था. उनके दृष्टिकोण में क्या कोई बदलाव आया है? इस सवाल के जवाब मेंबोल्टन कहते हैं कि ट्रंप मुख्य तौर पर मुद्दों को बहुत सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं. वह रणनीतिक रूप से नहीं सोचते हैं. बोल्टन का कहना है कि, ‘मुझे लगता है कि वह बड़ी डील की तलाश में है, ताकि वह चीन के साथ एक और आर्थिक व्यापार डील की तलाश कर सकें.

अमेरिकारू नए साल का जश्न मना रहे थे लोग, शख्स ने चढ़ाया ट्रक और की अंधाधुंध फायरिंग, 10 की मौत

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

दक्षिणी अमेरिकी शहर न्यू ऑरलियन्स में भीषण हादसा हुआ है. नए साल के पहले दिन एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक भीड़ में जा घुसा. इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है.

दक्षिणी अमेरिकी शहर न्यू ऑरलियन्स में भीषण हादसा हुआ है. नए साल के पहले दिन एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक भीड़ में जा घुसा. इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, लुइसियाना शहर के लो. कप्रिय पर्यटन स्थल फ्रेंच क्वार्टर में बॉर्बन स्ट्रीट पर भारी भीड़ जमा हुई थी. इसी दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भीड़ में ही ड्राइवर ट्रक से बाहर निकला और उसने फायरिंग शुरू कर दी. ये घटना सुबह करीब 3.15 बजे हुई.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारियों का कहना है कि जब बॉर्बन स्ट्रीट के चौराहे पर पिकअप ने भीड़ को टक्कर मारी, उस समय लोग नए साल का जश्न मना रहे थे. न्यू ऑरलियन्स पुलिस प्रवक्ता ने सीबीएस न्यूज को बताया कि शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चला है कि कार ने लोगों के एक समूह को टक्कर मार दी होगी. घायलों के बारे में पता नहीं है लेकिन कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है. लोगों से कैनाल और बॉर्बन स्ट्रीट के उस क्षेत्र से दूर रहने को कहा है, जहां यह घटना हुई.

पुलिस की लोगों से अपील

प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और कई सोशल मीडिया पोस्ट से ये बात सामने आई है कि हादसा बहुत ही भीषण था.

हादसे के बाद कई वीडियो फुटेज और तस्वीरों भी सामने आई हैं. इनमें पुलिस की गाड़िया, एंबुलेंस चौराहे के आसपास खड़े दिखाई दिए. अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं. पुलिस ने लोगों से कहा है कि वो अभी इस क्षेत्र में यात्रा करने से बचें.

इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा

ऑरलियन्स में हादसे के बाद हुई गोलीबारी की घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. अधिकारी जांच कर रहे हैं.

3 बच्चों को मारा, पत्नी की भी करना चाहता था हत्या... अब मिली सजा-ए-मौत

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

कर्नाटक की मंगलुरु में एक कोर्ट ने हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई है. उसने अपने तीन बच्चों की हत्या कर दी थी और अपनी पत्नी को कुएं में धकेलकर मारने की कोशिश भरसक कोशिश की थी. कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है. तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की जज संध्या ने 31 दिसंबर को हितेश शेट्टीगर को उसके जघन्य कृत्य के लिए सजा–ए–मौत दी है. पुलिस के अनुसार, घटना 23 जून, 2022 को पद्मनूर गांव में हुई थी. आरोपी ने कथित तौर पर अपने तीन बच्चों को कुएं में धकेल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई थी. उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी को भी उसी कुएं में धकेलकर हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गई और पूरा मामला खुल गया.

जांच में पता चला कि आरोपी बेरोजगार था और अक्सर अपनी पत्नी से झगड़ा करता रहता था. घटना वाले दिन, नाराजगी के कारण उसने अपराध करने से पहले अपने बच्चों के स्कूल से लौटने का इंतजार किया था. जैसे ही बच्चे स्कूल से लौटे उन्हें कुएं में धकेल दिया था और अपनी पत्नी को भी उसी कुएं में धकेला. महिला मदद के लिए चिल्लाई, तो पास में काम कर रहे एक फूल विक्रेता ने उसकी चीख सुनी और कुएं में उतकर उसे बचाया था.

हत्या और हत्या की कोशिश करने का मामला हुआ था दर्ज

जांच के दौरान पाया गया कि सबसे बड़ी बेटी ने कुएं में लगे पंप पाइप से चढ़कर बचने की कोशिश की थी, लेकिन हत्यारे बाप ने चाकू से पाइप को काट दिया और वह फिर से कुएं में गिर गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई. शिकायत के आधार पर मुल्की पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था. इंस्पेक्टर कुसुमाधारा के नेतृत्व में और एएसआई संजीव की सहायता से डिटेल जांच के बाद कोर्ट में आरोप पत्र पेश किए गए. अभियोक्ता मोहन कुमार ने मुकदमे के दौरान मजबूत सबूत पेश किए, जिससे आरोपी के अपराध की पुष्टि हुई.

26 जनवरी की परेड देखने के लिए कल से बुकिंग, अपने मोबाइल से घर बैठे टिकट पाएं

गणतंत्र दिवस करीब है. ऐसे में अगर आप इस खास मौके पर होने वाली परेड को देखना चाहते हैं तो इसके लिए घर बैठे ऑनलाइन टिकट की बुकिंग कर सकते हैं. इसके अलावा टिकट बुकिंग का ऑफलाइन विकल्प भी मौजूद रहेगा.

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

अगर आप दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट को लाइव देखना चाहते हैं तो इसके लिए टिकटों को 2 जनवरी 2025 से खरीदा जा सकेगा. 26 जनवरी 2025 के गणतंत्र दिवस परेड को देखने के लिए टिकटों की कीमत 20 और 100 रुपए तय की गई है. सबसे खास बात ये है कि आप घर बैठे मोबाइल की मदद से इसकी वेबसाइट पर जाकर अपने टिकट्स को बुक कर सकते हैं. गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन भारत की राजधानी नई दिल्ली में कर्तव्य पर हर साल भव्य परेड का आयोजन किया जाता है. यह परेड भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करती है. इस परेड में भारतीय सेना की विभिन्न शाखाओं, पुलिस बलों, स्कूली बच्चों और सांस्कृतिक समूहों के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां भी शामिल की जाती हैं.

कहां से करें टिकट की बुकिंग?

अगर आप पूरे देश की अलग–अलग झांकियों का आनंद एक दिन और एक जगह पर लेना चाहते हैं तो कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली इस परेड को देखने के लिए जा सकते हैं. टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए रक्षा मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. या फिर इस लिंक https:@@aamantran-mod-gov-in@login पर जाकर घर बैठे अपने मोबाइल से लॉगिन कर सकते हैं. लिंक पर क्लिक करने के बाद नीचे दिए गए हरे रंग पर के विकल्प पर क्लिक करें. क्लिक करने के बाद अपने मोबाइल नंबर और साइड में दिए गए कोड को भरें. फिर नीचे दिए ओटीपी के ऑप्शन को क्लिक करें और आपके मोबाइल फोन में आए ओटीपी को भरके आगे की प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं.

गणतंत्र दिवस परेड की इस टिकट बुकिंग सुविधा का लाभ मोबाइल ऐप के जरिए लिया जा सकता है. इसके लिए 'आमंत्रण' मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. वेबसाइट पर दिए गए क्यूआर कोड की इसमें मदद ली जा सकती है.

इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन मोड में परेड के लिए टिकट बुक कराना चाहते हैं तो सेना भवन के गेट नंबर–2 पर 2–5 जनवरी के बीच टिकट को खरीदा जा सकता है. शास्त्री भवन के गेट नंबर–3, जंतर–मंतर के मुख्य गेट के पास, प्रगति मैदान के गेट नंबर–1 और राजीव चौक के गेट नंबर–7 और 8 से भी परेड के टिकट को लिया जा सकता है.

'वो देखो चौथी मरने वाली है, सुबह तक मैं भी मर जाऊंगा...', लखनऊ में 5 कत्ल करते-करते अरशद बनाता गया वीडियो

लखनऊ सामूहिक हत्याकांड इस वक्त देशभर में सुर्खियों में बना हुआ है. मां और चार बहनों की हत्या करने वाला अरशद पुलिस की गिरफ्त में है. इस बीच उसका वीडियो सामने आया है, जिसे उसने वारदात को अंजाम देते वक्त बनाया था.

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

वो देखो मेरी अम्मी, बहनें और चौथी वाली बस मरने ही वाली है३ लखनऊ सामूहिक हत्याकांड के इस वीडियो को जिस किसी ने भी देखा उसकी रूह कांप गई. लाश के मुंह दुपट्टे से ढके हुए और हाथ की नसें कटी हुई दिखीं. कातिल ने खुद इस वीडियो को बनाया. साथ ही वो कहानी सुनाई जिसकी वजह से उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. कातिल अरशद ने वीडियो में सीएम योगी और पीएम मोदी से कुछ मांग भी की है.

लखनऊ में अल सुबह 5 मर्डर की खबर से पूरा शहर दहल गया था. होटल शरनजीत से पुलिस को फोन आया. बताया गया कि यहां एक लड़के ने पांच कत्ल कर दिए हैं. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. देखा कमरा नंबर–9 में खून से लथपथ हालत में 5 शव पड़े थे. आरोपी भी वहीं था. पुलिस ने तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी जल्द ही पुलिस के सामने टूट गया.

पुलिस को आरोपी ने बताया कि उसी ने ये पांच हत्याएं की हैं. आरोपी का नाम अरशद है. वो मूल रूप से बदायूं का रहने वाला है. लेकिन पिछले कई साल से वो और उसका परिवार आगरा में रह रहा था. आरोपी अरशद ने पुलिस को बताया– मैंने अपने मोहल्ले वालों से तंग आकर अपनी मां और चारों बहनों को मार डाला. मेरे पापा ने हत्याकांड में मेरा साथ दिया और वो अब सुसाइड करने गए हैं. कातिल की यह बात सुनकर पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए. उन्होंने तुरंत कातिल अरशद के पिता की तलाश शुरू की. अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं लग पाया है.

इस बीच पुलिस को कातिल का वो वीडियो भी मिल गया, जिसे उसने पांचों कत्ल को अंजाम देने के दौरान बनाया था. इस वीडियो में कातिल ने खुद चार लाश दिखाईं. बोला– ये देखो ये मेरी अम्मी है, ये मेरी तीन बहनें. ये सभी मर चुकी हैं. इसके बाद कातिल ने कैमरा घुमाया. एक और लड़की के मुंह पर किसी शख्स ने हाथ रखा. ये हाथ कातिल के पिता ने ही लड़की के मुंह पर रखा था ताकि उसका शोर किसी को सुनाई न दे. कातिल बोला– ये चौथी है, ये भी मरने वाली है. इसके बाद सुबह तक मैं भी मर जाऊंगा.

बांग्लादेशी कहकर चिढ़ाते हैं

अरशद ने वीडियो में कहा– मेरी बस्ती के मुसलमान लोगा. ` ने मेरे आधे प्लॉट पर कब्जा कर लिया है. वो पूरे प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं. हम लोग इसका विरोध करते थे. वो लोग हमें फिर इसी बात को लेकर तंग करने लगे. पड़ोस में रहने वाला एक शख्स मेरी बहन को हैदराबाद में बेचने का प्लान बना रहा था. हम लोग हिंदू धर्म अपनाना चाह रहे थे ताकि इन लोगों से हमें छुटकारा मिल जाए. हमने कई लोगों से मदद मांगी. लेकिन किसी ने भी हमारी मदद नहीं की. न पुलिस ने, न बजरंग दल ने और न ही किसी बीज. `पी के नेता ने.

पड़ोसी हमें बांग्लादेशी कहकर टॉर्चर देते थे. जबकि, हम लोग 1947 से बदायूं में ही रह रहे हैं. मेरे दादा से लेकर परदादा तक.

बीजेपी के घोषणापत्र में है यूसीसी, बोले कानून मंत्री मेघवाल- विधि आयोग के पास लंबित

जम्मू लद्दाख विज़न ब्यूरो

पीएम मोदी ने कहा था कि उस दौर की बहसों के दौरान संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य केएम मुंशी ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर देश में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत बताई है.

देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर चर्चा हुई. मेघवाल ने कहा कि यूसीसी गोवा में लागू किया जा रहा है और उत्तराखंड ने इसके लिए कानून बनाया है. यूसीसी बीजेपी के घोषणापत्र का हिस्सा था, इसमें कोई संदेह नहीं है. जब हमें लगता है कि यह संभव है तो हम घोषणापत्र में चीजें लेते हैं. राज्यों ने भी इस पर काम किया. अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह पहले से ही गोवा में लागू था और उत्तराखंड ने अधिनियम पारित किया. मामला भारत के विधि आयोग के पास लंबित है, अन्य राज्य भी इसमें रुचि रखते हैं. उन्होंने इस साल की शुरुआत में गठित 23वें विधि आयोग के संदर्भ की शर्तों में समान नागरिक संहिता शामिल थी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की शुरुआत में संसद में कहा था कि सरकार धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता लाने के लिए अपना ताकत लगा रही है. उन्होंने लोकसभा में भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर आयोजित एक बहस में अपने भाषण के दौरान यह टिप्पणी की. पीएम मोदी ने कहा कि एक ज्वलंत मुद्दा है जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं और वह है समान नागरिक संहिता. इस विषय को संविधान सभा ने भी नजरअंदाज नहीं किया.

समान नागरिक संहिता पर चर्चा

संविधान सभा ने समान नागरिक संहिता पर लंबी और गहन चर्चा की थी. कठोर बहस के बाद निर्णय लिया गया कि जो भी सरकार देश में समान नागरिक संहिता चुने उसके लिए बेहतर होगा की भविष्य में वह इस विषय पर निर्णय लेकर उसे क्रियान्वित करें. यह बत संविधान सभा ने और स्वयं डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर ने कहा था.

पीएम मोदी ने कहा था हालांकि, जो लोग न तो संविधान को समझते हैं और न ही देश को. उन लोगों ने सत्ता के लिए अपनी भूख से परे कुछ भी नहीं पढ़ा है. पीएम मोदी ने कहा था डॉ. बाबासाहब अम्बेडकर ने पर्सनल लॉ को ख़त्म करने की पुरजोर वकालत की थी जो धार्मिक आधार पर आधारित थे.

देश की एकता के लिए न्ब्ब जरूरी

पीएम मोदी ने कहा था कि उस दौर की बहसों के दौरान संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य केएम मुंशी ने इस बात पर ज़ोर दिया था कि राष्ट्र की एकता और आधुनिकता के लिए समान नागरिक संहिता जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर देश में जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता लागू करने की जरूरत बताई है और सरकारों को इस दिशा में काम करने का निर्देश भी दिया है.

संविधान की भावना और संविधान निर्माताओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता स्थापित करने की दिशा में पूरी ताकत से काम कर रहे हैं. पीएम मोदी ने इस साल स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में भी समान नागरिक संहिता के बारे में बात की थी.

देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग

पीएम मोदी ने कहा था कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को साकार करें. हमें विविध विचारों और दृष्टिकोणों का स्वागत करना चाहिए.

हमारे देश को धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले और भेदभाव को बढ़ावा देने वाले कानूनों का आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है.

इसलिए, मैं जोर देकर कहता हूं कि देश के लिए धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की मांग करने का समय आ गया है.